Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 34
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
मंगलवार, 10 फरवरी, 2026

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 संजय राउत का सलमान खान और आरएसएस... 4 डील बदली, दिशा बदलीः मोदी युग में भारत ... 7 वेलोसिटी का एआई शिपिंग पर बड़ा दांव...

संक्षिप्त न्यूज

पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी, 2500 रूपये देने का होगा वादा!

कोलकाता। भाजपा पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए लाडली योजना की तर्ज पर बड़ा वादा कर सकती है। पार्टी विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में बंगाल की हर महिला मतदाता को हर महीने 2500 रूपये के नकद आर्थिक भुगतान करने की घोषणा कर सकती है। बिहार चुनाव में इसी तरह के वादे ने कमाल कर दिया था और भाजपा-जेडीयू गठबंधन बड़े बहुमत से सरकार बचाने में सफल रहा था। बंगाल में भी इसी तरह का मॉडल पेश कर पार्टी बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक लाख महिला मतदाताओं को लखपति दीदी बनाने, ड्रोन दीदी रोजगार से जोड़ने और गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना सुविधा देने की घोषणा कर सकती है।

भारतीय जनता पार्टी इस समय पश्चिम बंगाल में मतदाताओं से चुनाव संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) तैयार करने के लिए सुझाव ले रही है। फरवरी महीने के अंत में पार्टी अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रख सकती है। इस संकल्प पत्र में ऐसी बड़े वादे किए जाने की संभावना है जो राज्य की चुनावी बिसात पर भाजपा को मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। महिला मतदाता भाजपा की विशेष समर्थक वर्ग के रूप में उभरी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर जहां महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत अधिक था, उनमें से सबसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन ने ही जीता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं ने भाजपा को बढ़-चढ़कर वोट किया था। यह रुझान 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बना रहा।

फिर हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा में बजट पर चर्चा

नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इस मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ था कि केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए। इस बीच, राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हो चुकी है। पिछले सप्ताह, लोकसभा ने प्रधानमंत्री के पारंपरिक उत्तर के बिना, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के साथ-साथ सदन द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपना भाषण देने की अनुमति न दिए जाने के विरोध में विपक्ष के मुखर विरोध के बीच, ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। वहीं, संसद के दोनों सदनों में पिछले सप्ताह शुक्रवार को अंडर-19 क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम को सोमवार को बधाई दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा में बजट पर चर्चा से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अन्य विषय पर आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बीच कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले अपनी बात रखने की अनुमति देने का वादा किया है, वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि कांग्रेस नेता की बात शत-प्रतिशत सही नहीं है और अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता से कहा था कि पहले वह विषय बताएं जो वह सदन में उठाना चाहते हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने

सोमवार को कुछ अन्य विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाक़ात की और उन्हें उन मुद्दों से अवगत कराया जिन्हें वे सदन में उठाना चाहते हैं। यह बैठक कुछ ही मिनट चली। यह उस समय हुई जब लोकसभा में बजट पर चर्चा से पहले राहुल गांधी को अन्य विषय पर आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बीच कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस ने विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी संबंधी खबरों को लेकर सोमवार को कहा कि 'कार्रवाई का इंतजार कीजिए।' पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि अब सदन में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं रह गई है।

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने घटते पूंजीगत व्यय पर चिंता जताते हुए कहा कि आम बजट 2026-27 में इसे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है तथा यह एक ऐसा बजट है जिसे भुला दिया जाना चाहिए। उच्च सदन में चिदंबरम ने बजट 2026-27 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बजट में आवंटित धन पर सवाल उठाते हुए रक्षा, विज्ञान, सामाजिक कल्याण और शहरी विकास में कटौती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन उनका आवंटन कम था या घोषित ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह बजट सतर्क, कंजूस और बीते साल की अनदेखी करने वाला है, और यह जल्द ही गायब हो जाएगा।

राज्यसभा में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने की अनुमति न मिलने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। उच्च सदन में जब शून्यकाल समाप्त हुआ और प्रश्नकाल शुरू हुआ तब कांग्रेस सदस्य खरगे ने अपनी बात रखनी चाही। आसन से स्वीकृति मिलने पर खरगे ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों को मिला कर संसद बनती है और संविधान का पालन सबको करना होता है।

राज्यसभा में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उसे आगाह किया कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) लागू करने का जो प्रयास कर रही है, वह उस पर उलटा पड़ेगा।

शशि थरूर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

बोले-सदन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और लोकसभा अध्यक्ष पर संसद चलाने में रुचि न रखने का आरोप लगाया और कहा कि लोकसभा में बार-बार व्यवधान के कारण वे केंद्रीय बजट 2026-27 पर बोलने में असमर्थ रहे। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि वे बजट पर चर्चा में भाग लेने की तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार और लोकसभा अध्यक्ष सदन चलाने में रुचि नहीं रखते हैं।

शशि थरूर ने आगे कहा कि वे दिन में बाद में फिर से बोलने का प्रयास करने के लिए लौटेंगे। थरूर ने कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अनुपस्थिति की ओर भी इशारा किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थगन की आशंका पहले से ही थी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सदन में बैठी ही नहीं थीं और आगे कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि सदन स्थगित होगा। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रहने का कार्यक्रम था। यह बजट सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर, थरूर ने कहा कि यह फैसला उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है; आप इस बारे में हाई कमांड से पूछ सकते हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय कार्यवाही को लेकर जारी गतिरोध के बीच, विपक्षी सांसद बजट सत्र के दूसरे भाग में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं।

तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, राज्य के विकास और फंडिंग पर उठाए गंभीर सवाल

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि दक्षिणी राज्यों को उनका हक का फंड नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार के नगरपालिका चुनावों में तीन राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा में हैं बीआरएस, जो पिछले दस वर्षों से राज्य में सत्ता में है, भाजपा, जो केंद्र में सत्ता में है और कांग्रेस, जो राज्य में सत्ता में है।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाबूबनगर आए और पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा किया। मैं इंतजार कर रहा था कि यह वादा पूरा होगा या नहीं, उसके बाद वोट मांगूंगा। वहीं, देवेंद्र फडणवीस आदिलाबाद में आए और प्रनाहिता-चेवेला परियोजना के वादे को पूरा करने के बजाय वोट मांगने आए।

मणिपुर के उखरूल में फिर भड़की हिंसा; 21 घर जलाए, शांति बहाली की कोशिश में जुटा प्रशासन

इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के उखरुल जिले में सोमवार दोपहर को एक बार फिर हिंसा भड़क गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हिंसा तब भड़की जब कथित तौर पर हथियारबंद बदमाशों ने लिटन सरेखोंग गांव में कई घरों को आग लगा दी। इस दौरान हमलावरों ने हवा में गोलियां भी चलाईं। इस डर से ग्रामीण अपना जरूरी सामान लेकर पड़ोसी जिले कांगपोकपी के सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। कई तांगखुल ग्रामीणों ने भी अपना घर छोड़ दिया है।

क्या है मामला?

इस हिंसा की शुरुआत शनिवार रात को हुई थी। तब लिटन गांव में सात-आठ लोगों ने तांगखुल नागा समुदाय के एक व्यक्ति पर हमला किया था। हालांकि, पीड़ित पक्ष और गांव के मुखिया ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया था। रविवार को इस पर एक बैठक होनी थी, लेकिन वह बैठक नहीं हो पाई।

इसके बजाय, पास के सिकिबुंग गांव के लोगों ने लिटन सरेखोंग के मुखिया के घर पर हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक, ग्रामीणों ने पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग भी की। रविवार रात को दो समूहों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद प्रशासन ने पाबंदी लगा दी। इसके बाद सोमवार आधी रात को तांगखुल नागा समुदाय के घरों में आग लगा दी गई। इसका आरोप कुकी उग्रवादियों पर लगा है। इसके बाद कुकी समुदाय के भी कुछ घर जलाए गए।

क्या बोले राज्य मंत्री?

राज्य मंत्री गोविंददास कोंथौजम ने बताया कि हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। सोमवार सुबह तक 17 घर जले थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 21 हो गई है। उपमुख्यमंत्री एल डिखो मौके पर मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। शांति बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं।

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

शांति के लिए एक बड़ी बैठक भी हुई। इसमें तांगखुल नागा लॉन्ग, असम राइफल्स के अधिकारी, विधायक और कुकी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और हिंसा रुकनी चाहिए। उन्होंने इसे कुछ लोगों की शरारत बताया और इसे बड़ा रूप न देने की अपील की।

लोकसभा में रारः राहुल का दावा-

अध्यक्ष ने बोलने का दिया था आश्वसन, अब वह वादे से मुकर रहे; रिजिजू ने किया खंडन

नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को हंगामे के बीच दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे पर चर्चा की मांग जारी रखने के चलते सदन को फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें कुछ बिंदु रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष अपने वादे से पीछे हट रहे हैं।

'लोकसभा अध्यक्ष अपने वादे से पीछे हट रहे हैं'

राहुल गांधी ने कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही सांसद संध्या राय से कहा, अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से हमसे वादा किया था कि मुझे बजट पर चर्चा से पहले यहां बोलने की अनुमति दी जाएगी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे उन मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं?

राहुल के दावे पर क्या बोले रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा राहुल गांधी ने कहा कि वेणुगोपाल जी स्पीकर के चैंबर में थे। मैं भी शामिल हुआ और हमने चर्चा की। मैं यह कन्फर्म करना चाहता हूं कि स्पीकर ने यह पहल किया कि अगर सब सहमत हों, तो सदन चलना चाहिए और वेणुगोपाल जी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता कुछ कहें। लेकिन उससे पहले, हमने तय किया कि आप किस टॉपिक पर बोलेंगे?... स्पीकर ने यह कहा कि राहुल गांधी ने अभी जो कहा वह 100 परसेंट सही नहीं है। स्पीकर ने कोई वादा नहीं किया है। स्पीकर ने कहा कि अगर कोई समझौता होता है, तो हम आपको बोलने देंगे और हम दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी बोलने देंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस को ही बोलने देंगे...।

'लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव', विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला पर आवाज दबाने का आरोप लगाया

विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। उनका आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रतिक्रिया दी है और इसे संसद की परंपरा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला करे। सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है इसलिए उन्होंने ये कहा है क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की। इसलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं, ये गलत बात है।

'व्हाट्सएप पर लगे रोक, हटाए जाएं माइक्रो ऑब्जर्वर'

ममता सरकार ने की एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव की मांग

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को कहा कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी प्रक्रिया में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तृणमूल सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया कई मतदाताओं को वंचित कर सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा निशाना बनाया गया है।

सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि यह प्रक्रिया (एसआईआर) बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित कर सकती है और इसमें पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को अनुचित रूप से निशाना बनाया गया है।

क्या ममता सरकार की मांग?

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ममता सरकार ने मांग की है कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर निर्देश देना बंद करे। सभी आदेश आधिकारिक लेटरहेड, मेमो नंबर और तारीख के साथ होने चाहिए। इन निर्देशों को आयोग की वेबसाइट पर भी डालना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इसे 'व्हाट्सएप

कमीशन' बताते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं।

सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया से माइक्रो ऑब्जर्वर को पूरी तरह हटा दिया जाए। उनकी जगह राज्य के 8,505 ग्रुप बी अधिकारियों को काम पर लगाया जाए। सरकार का तर्क है कि नाम काटने का आखिरी फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) के पास ही होना चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वर के फैसलों को रद्द करने का अधिकार भी ईआरओ को मिलना चाहिए।

रखी ये मांगें

राज्य ने अदालत से कहा है कि नाम में छोटी-मोटी गलती के आधार पर किसी का वोट न काटा जाए। साथ ही घर के अलॉटमेंट लेटर को पते के सबूत के तौर पर माना जाए जैसा बिहार में हुआ था। ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया की तेज रफ्तार पर भी सवाल उठाए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया है कि 2022 की वोटर लिस्ट में शामिल मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।

अजित डोभाल के दौरे से भारत और कनाडा रिश्तों में आई नई गर्माहट, दोनों देश मिलकर सिखाएंगे खालिस्तानियों को सबक

नई दिल्ली। भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कुछ समय से चला आ रहा तनाव अब कम होता दिख रहा है। इस बदलाव के केंद्र में हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की हालिया कनाडा यात्रा, जिसने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को नई दिशा दी है। यह यात्रा भरोसे की फिर से स्थापना और साझा हितों पर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत थी।

हम आपको बता दें कि अजित डोभाल ने ओटावा में कनाडा के शीर्ष सुरक्षा और नीति अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की। इन बैठकों में दोनों देशों ने एक साझा कार्य योजना पर सहमति जताई जिसका मकसद सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करना है। तय हुआ कि दोनों देश अपने सुरक्षा और कानून प्रवर्तन तंत्र के बीच सीधा संपर्क बढ़ाएंगे, लायजन अधिकारी तैनात करेंगे और सूचनाओं का तेज आदान-प्रदान सुनिश्चित करेंगे।

बातचीत के प्रमुख विषयों में साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, ड्रग तस्करी, अवैध वित्त प्रवाह, आव्रजन से जुड़ी धोखाधड़ी और ट्रांसनैशनल अपराध शामिल रहे। खास जोर इस बात पर रहा कि नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अपराध करने

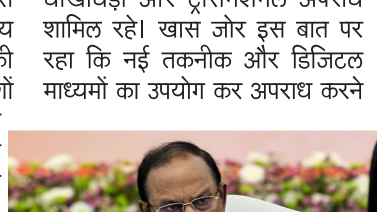

वाले नेटवर्क से मिलकर निपटा जाए। कनाडा की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि उसकी जमीन का उपयोग किसी भी तरह की हिंसक अलगाववादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह बात भारत के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि लंबे समय से भारत कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्वों को लेकर चिंता जताता रहा है।

गौरतलब है कि 2023 में एक खालिस्तानी उग्रवादी की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तीखा तनाव आया था। आरोप और प्रत्यारोप चले, राजनयिक स्तर पर कड़वाहट बढ़ी और भरोसे में कमी आई। ऐसे माहौल में डोभाल की यह यात्रा एक भरोसा बहाल करने वाला कदम मानी जा रही है।

अब संकेत साफ हैं कि दोनों देश मतभेदों को पीछे छोड़कर व्यावहारिक सहयोग की राह पर चलना चाहते हैं। आने वाले समय में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी रिश्तों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा को भी इसी क्रम में देखा जा रहा है, जो इस नई समझ को और मजबूती दे सकती है। देखा जाए तो अजित डोभाल की कनाडा यात्रा का महत्व केवल कागजी समझौतों में नहीं, बल्कि उसके सामरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। यह यात्रा तीन स्तर पर असर डालती दिखती है।

कर्नाटक कांग्रेस संकट गहरायाः

शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की फिर उठी मांग, 80 से 90 विधायकों के समर्थन का दा

बंगलूरू। कर्नाटक कांग्रेस में जारी नेतृत्व संकट और गहराता जा रहा है। उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सीधे तौर पर शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का अवसर देने की मांग की है। इकबाल हुसैन ने कहा, आप समानता और समाजवाद की बात करते हैं, अब समय आ गया है कि उस विचारधारा को अमल में लाया जाए।

हमारे नेता को भी एक अवसर मिले-हुसैन

सोमवार को बंगलूरू में पत्रकारों से बातचीत में हुसैन ने कहा, हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारे नेता को भी एक अवसर मिले। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हमेशा समाजवाद, समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा नेता हूं, लेकिन आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने सिद्धांतों को व्यवहार में उतारें।

'करीब 80 से 90 विधायकों ने एक साथ यह इच्छा जताई'

उन्होंने कहा कि यह इच्छा केवल उनकी नहीं, बल्कि कई विधायकों की है और इसे पार्टी के अंदरूनी मंचों पर लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने अवसर की मांग की है। करीब 80 से 90 विधायकों ने एक साथ यह इच्छा जताई है कि इस कार्यकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आगामी चुनाव हम शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दोनों के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार राज्य में फिर से सत्ता में लौटे। इस चरण में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 7.5 साल तक इस पद पर रह चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने पांच साल पूरे किए और इस बार 2.5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने अच्छा शासन दिया है। इस बीच, शिवकुमार के एक अन्य करीबी और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एच.सी. बालकृष्ण ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पिता पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

बालकृष्ण ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री के बेटे यतींद्र ने बयान दिया है, नेतृत्व में होने वाले बदलाव रुक नहीं जाएंगे। जब फैसला होगा, तब मामला सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि यतींद्र को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

ढोकी पंचायत में कड़े मुकाबले में शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार ने भाजपा को हराया, एक वोट से हासिल की जीत

दिव्यांश

छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र में सोमवार को 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों के लिए मतगणना जारी है। अधिकारियों ने बताया कि धाराशिव जिले की ढोकी पंचायत समिति के चुनाव में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रतिद्वंद्वी को केवल एक वोट से हराया। ढोकी पंचायत समिति के चुनाव में कड़े मुकाबले में अमर समुद्रे ने जीत हासिल की। यह जीत मतपत्रों की गणना के बाद मिले दो अतिरिक्त वोटों से तय हुई। अमर समुद्रे को कुल 3,187 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंद्वी निहाल काजी (भाजपा) को 3,186 वोट मिले। इसके अलावा, नोटा के लिए 56 वोट पड़े।

किन जिलों में हुए चुनाव?

चुनाव आयोग के मुताबिक, 731 जिला परिषदों और पंचायत समिति की 1,462 सीटों के लिए कुल 7,438 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर जिलों में हुए।

चुनाव में देरी क्यों हुई?

चुनाव पहले पांच फरवरी को होना था। लेकिन 28 जनवरी विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन और इसके बाद तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा के कारण इसे स्थगित किया गया। मतदान शनिवार सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे तक चला। मतगणना आज सुबह दस बजे शुरू हुई।

कुल कितने पुरुष और महिलाएं मतदाता?

मतदाता सूची में 1,06,33,269 पुरुष, 1,01,86,965 महिलाएं और 468 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। राज्यभर में कुल 25,471 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। चुनाव ड्यूटी के लिए लगभग 1.28 लाख कर्मियों को तैनात किया गया था, जिसमें 125 निर्वाचन अधिकारी और 125 सहायक निर्वाचन अधिकारी शामिल थे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) उपलब्ध कराई थीं, जिसमें 51,537 कंट्रोल यूनिट और 1,10,329 बैलट यूनिट शामिल हैं। अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। प्रत्येक मतदाता ने दो वोट डाले थे- एक जिला परिषद और एक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए। जिला परिषद का बैलट सफेद बैलट यूनिट पर था, जबकि पंचायत समिति का बैलट गुलाबी बैलट यूनिट पर था।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, गले में संक्रमण के बाद इलाज के अस्पताल में भर्ती

दिव्यांश

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, 85 वर्ष, को सोमवार दोपहर गले में खराश और खांसी की शिकायत के बाद बारामती स्थित उनके आवास से पुणे के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था। एनसीपी (एसपी) प्रमुख के भतीजे श्रीनिवास पवार ने बताया कि पवार को कल रात से लगातार खांसी आ रही थी और सीने में जकड़न के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पुणे ले जाया गया। रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ और प्रबंध न्यासी डॉ. परवेज़ ग्रांट ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। डॉ. ग्रांट ने कहा कि पहुँचने पर डॉक्टरों की एक टीम उनकी जाँच करेगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शरद पवार मुख कैंसर से उबर चुके हैं, जिसका निदान 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ था। उन्होंने इस बीमारी के इलाज के लिए अमेरिका और भारत में कई सर्जरी करवाईं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता रोहित पवार ने शनिवार को कहा कि हवाई दुर्घटना में अजित पवार की मौत की परिस्थितियों के बारे में सभी को संदेह है और वह 10 फरवरी को इस बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति देंगे। बारामती में जिला परिषद चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि अजित पवार चाहते थे कि राकांपा के दोनों गुट एकजुट हो जाएं और विलय की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव शनिवार को हुए। यह मतदान मूल रूप से पांच फरवरी को होना था, लेकिन 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु और इसके बाद तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

दिवंगत राकांपा प्रमुख के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि हर किसी के मन में (दुर्घटना के बारे में) सवाल और संदेह हैं। मैं 10 फरवरी को मुंबई में एक प्रस्तुति दूंगा। दुर्घटना क्यों हुई और यह कैसे हुई होगी, ये मुद्दे 10 फरवरी को उठाए जाएंगे। जिला परिषद चुनाव के लिए राकांपा (शप) और राकांपा ने हाथ मिलाया है और दोनों 'घड़ी' चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार राकांपा के प्रमुख थे, जबकि उनके चाचा शरद पवार राकांपा (शप) के प्रमुख हैं।

भुसावल मंडल ने की अनाधिकृत और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कारवाई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के दौरान अनाधिकृत और बिना टिकट यात्रा करने वाले 08.18 लाख यात्रियों से 68.86 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

भुसावल मंडल अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के तहत, अपने पूरे नेटवर्क में अनाधिकृत और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज कर रहा है। संगठित और व्यवस्थित टिकट जांच अभियानों के माध्यम से, भुसावल मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भुसावल मंडल की समर्पित टिकट जांच टीमों ने बिना टिकट, अनुचित या अमान्य यात्रा प्राधिकरण के साथ यात्रा कर रहे 08.18 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यह संख्या 05.82 लाख थी, जो लगभग 40इ की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जुर्माने के रूप में रिकॉर्ड 68.86 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 42.87 करोड़ रुपये वसूले गए थे, जो 61% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

भुसावल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से जनवरी 2026) के लिए बिना टिकट/वैध टिकट के यात्रा करते पकड़े गए जिसमे 08.18 लाख यात्रियों को पकड़ा और उनसे 68.86 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूल की गई। भुसावल मंडल अनधिकृत यात्रा का पता लगाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाता है, जिसमें स्टेशन चेक, अंबुस चेक, किलेबंदी चेक, गहन चेक और मेगा टिकट चेकिंग अभियान शामिल हैं। ये अभियान मंडल में चलाए जाते हैं, साथ-साथ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, स्पेशल ट्रेनों में चलाए जाते हैं।

भुसावल मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अधिकृत विक्रेताओं द्वारा जारी वैध टिकटों के साथ, रेलवे स्टेशन बुकिंग काउंटरों से, एटीवीएम के माध्यम से या वेबसाइट http://www.irctc.co.in या रेलवन ऐप के माध्यम से टिकट बुक करें।

यात्रियों से अपील करते है कि वे असुविधा और जुर्माने से बचने के लिए उचित और वैध टिकट खरीदकर सम्मान और जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें।

वायु गुणवत्ता सुधार के लिए सख्त उपाय लागू करने के निर्देश

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू की जा रही व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएँ। विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक में आयुक्त ने पर्यावरण, अतिक्रमण, स्वच्छता व शौचालय प्रबंधन, संपत्ति कर, जल शुल्क और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता, प्रशासन विभाग के उप आयुक्त सहित अन्य विभाग प्रमुख, अधिकारी और कार्यकारी अभियंता उपस्थित थे।

आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर निगम द्वारा घोषित मानक कार्यप्रणाली के अनुसार निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण रोकथाम उपायों के क्रियान्वयन के दौरान संबंधित अधिकारी और प्रभाग स्तर पर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाए। नियमों का उल्लंघन होने पर नोटिस जारी किया जाए और अनदेखी होने पर स्थल पर कार्य रोक दिया जाए। इसके अनुरूप की गई कार्रवाई की विभागवार समीक्षा की गई। बड़े निर्माण स्थलों के साथ-साथ अन्य निर्माण स्थलों का भी निरीक्षण कर वहाँ नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों के स्थलों का भी निरीक्षण कर

नियमों के पालन की पुष्टि की जाए।

आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी छोटे-बड़े निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण लगाना अनिवार्य है तथा उसकी जानकारी ऐप पर एकीकृत की जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि ये उपकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृत अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदे जाएँ, ताकि सूचकांकों की विश्वसनीयता बनी रहे।

निर्देश दिए गए कि विभाग कार्यालय स्तर पर निरीक्षण दल गठित किए जाएँ, जो यह जाँच करें कि निर्माण स्थल नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं, और इनके माध्यम से नियमित निरीक्षण जारी रखा जाए। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रभावी और सख्त क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रभाग आयुक्त और विभाग अधिकारियों की होगी, और उनके माध्यम से अधिक ठोस कार्रवाई की जाए।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के सुझाव

आयुक्त ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान को और अधिक तीव्र एवं गतिशील ढंग से लागू करने के निर्देश दिए तथा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। इस संबंध में उड़नदस्ते शीघ्र गठित कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छता और शौचालय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

चल रहे गहन सफाई अभियानों के दायरे को बढ़ाने और उनमें नियमितता बनाए रखने के निर्देश देते हुए आयुक्त ने सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की सुविधाओं का निरीक्षण करने तथा वहाँ निरंतर स्वच्छता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। नगर निगम में हाल ही में शामिल किए गए गाँवों में भी स्वच्छता और सुविधाओं को लेकर सक्रिय कदम उठाने के संकेत दिए गए।

संपत्ति कर और जल कर वसूली लक्ष्य को पूरा करने की योजना तथा ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं के व्यापक प्रचार के निर्देश

आयुक्त ने विभागों को सलाह दी कि पूर्व समीक्षा बैठक में दिए गए संपत्ति कर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना और कार्रवाई शुरू करें तथा बकाया वसूली पर भी नजर रखें। जल शुल्क वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

नागरिकों को संपत्ति कर और जल शुल्क भरने के लिए नगर निगम के किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए नगर निगम ने कई ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इससे नागरिकों का समय, श्रम और खर्च बच रहा है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि इन सभी विकल्पों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से नागरिकों तक व्यापक रूप से पहुँचाई जाए।

नगर निगम ने सरकारी कार्यालय सुधार कार्यक्रम में राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। रैंकिंग को और बेहतर बनाने के लिए आयुक्त ने निर्देश दिए कि सरकारी सेवाओं की प्रतिक्रिया समय और शिकायत निवारण प्रणाली को और कैसे कम किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्य करते समय अधिक निरंतरता लाने का भी सुझाव दिया गया।

जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से समग्र शहर विकास

हाल ही में महापौर-उपमहापौर चुनाव संपन्न हुए हैं और जनप्रतिनिधि सक्रिय हुए हैं। आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रमुख उनके साथ अच्छा समन्वय बनाए रखें, नगर निगम के माध्यम से चल रहे कार्यों की जानकारी उन्हें दें तथा शहर के विकास के लिए मिल-जुलकर और सहयोग से कार्य करें।

पश्चिम रेलवे के 10 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, वडोदरा एवं भावनगर मंडलों के कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार द्वारा 09 फरवरी, 2026 को पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में आयोजित एक समारोह में दिसंबर 2025 के लिए 10 कर्मचारियों को महाप्रबंधक का 'मैन ऑफ द मंथ' सेफ्टी अवॉर्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों को उनकी असाधारण सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के लिए सम्मानित किया गया, जिससे संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। सम्मानित कर्मचारियों में अहमदाबाद मंडल से पाँच, वडोदरा एवं भावनगर मंडल से दो-दो तथा मुंबई सेंट्रल मंडल से एक कर्मचारी शामिल थे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल में फ़िटर के पद पर कार्यरत श्री शिवलाल को उनकी असाधारण सतर्कता एवं संरक्षा के प्रति समर्पण के

लिए महाप्रबंधक का सेफ्टी अवॉर्ड प्रदान किया गया। दिसंबर 2025 के दौरान, बांद्रा शेड में एक लोकोमोटिव के नियमित निरीक्षण के समय उन्होंने पहिए में एक दोष का पता लगाया और तुरंत इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी। समय पर की गई उनकी इस कार्रवाई से त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए गए तथा असुरक्षित ट्रेन परिचालन एवं मार्ग में होने वाली संभावित अप्रिय घटना को सफलतापूर्वक टाल दिया गया।

अहमदाबाद, वडोदरा एवं भावनगर मंडलों से सम्मानित कर्मचारियों को भी उनकी असाधारण सूझबूझ, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता तथा त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों ने रेल फ्रैक्चर, ट्रैक पर अवरोध, ब्रेक के अधिक गर्म होने, वैगन में दोष तथा उपकरणों में असामान्यताओं जैसी गंभीर संरक्षा संबंधी कमियों का समय रहते पता लगाया। इन सभी के सामूहिक प्रयासों से पश्चिम रेलवे में उच्च स्तर की संरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

पश्चिम रेलवे सभी सम्मानित कर्मचारियों की उनके कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय समर्पण एवं सुदृढ़ सुरक्षा चेतना की सराहना करती है। इनके कार्यों से न केवल संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सका, बल्कि सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेल परिचालन के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ किया गया। साथ ही, ये सभी कर्मचारी अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं।

बेरछ स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण जयपुर-उदयपुर सिटी स्पेशल प्रभावित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के अंतर्गत बेरछ स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य के कारण रतलाम मंडल से गुजरने वाली जयपुर-उदयपुर सिटी स्पेशल प्रभावित रहेगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 10 फरवरी 2026 को जयपुर से

चलने वाली गाड़ी संख्या 09721 जयपुर-उदयपुर सिटी स्पेशल चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा चंदेरिया से जयपुर तक निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा गोल्डन टेम्पल मेल के टर्मिनल में अस्थायी परिवर्तन की अवधि बढ़ाई गई

गोल्डन टेम्पल मेल अगले छह महीनों तक बांद्रा टर्मिनस से ही ओरिजिनेट/टर्मिनेट होगी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे ने गोल्डन टेम्पल मेल के टर्मिनल से संबंधित अस्थायी परिचालन व्यवस्था को अगले छह माह तक जारी रखने की अधिसूचना जारी की है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 12903 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल आगामी 17 अगस्त 2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से ही ओरिजिनेट होती रहेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 12904 अमृतसर-मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेम्पल मेल आगामी 15 अगस्त 2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस पर ही टर्मिनेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के ठहराव के समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु IREPS पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं: **निविदा क्रमांक: EL/TRD/58/2025-26/22, दिनांक 06.02.2026. कार्य का नाम:** TRD Work in connection with electrification work between Chanderiya (CNA)-Ajmer (All). **अनुमानित लागत:** रु. 5,65,37,300/-. **बयाना राशि:** रु.4,32,700/-. **समापन अवधि:** 12 Months. **निविदा दस्तावेज़ की राशि:** Nil. **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय:** 02.03.2026 at 15:00 hrs. **ऑफर की वैधता:** 60 days from the date of opening. **वेबसाइट: www.ireps.gov.in. नोटिस बोर्ड:** वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने। SPAN/13/1/450

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

निरस्तीकरण सूचना

निविदा क्रमांक : BCT/25-26/307 दिनांक : 29/01/2026 DOP : 24/02/2026 को तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है। 1104

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

रखरखाव कार्य

वरिष्ठ मंडलीय विद्युत अभियंता (उप), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल द्वारा ई-निविदा क्रमांक : WR-MMCTOESUB (ESPT)/19/2025आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम** : मुंबई उपनगरीय खंड में चर्चगेट-विरार सेक्शन के बीच पीएसआई प्रणाली में 110/25 केवी एसी उपकरणों का वार्षिक अनुसूचित रखरखाव कार्य तथा सभी टीआरडी उपकरणों की थर्मो विज़न जाँच। **कार्य की अनुमानित लागत** : 2,13,56,350/- **बोली सुरक्षा (बिड सिक्योरिटी)** : 2,56,800/- **बोली जमा करने की अंतिम तिथि व समय** : 02.03.2026 तक, 15:00 बजे। बोली खोलने की तिथि व समय : 02.03.2026 को, 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1091

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

पुल का मजबुतीकरण

ई-निविदा सूचना सं.

DRM-BRC 176 OF 2025-26

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (W A/C.), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004 द्वारा निम्नानुसार कार्यों हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम:** डभोई-एकतानगर अनुभाग :- कि.मी. 30.00 अंतर्गत मौजुदा पुल सं. 58 का सूचित मजबुतीकरण। **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में):** 16,10,48,715.27, **जमा कराने की बीड सुरक्षा (₹ में):** 9,55,300.00, **निविदा जमा कराने एवं निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा दिनांक 27/02/2026 को 15:00 बजे से पहले जमा की जाएगी एवं उसी दिनांक को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी। **वेबसाईट का विवरण एवं नोटीस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं एवं कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीद सकते हैं:** वेबसाईट: @ www.ireps.gov.in मंडल रेल प्रबंधक (W A/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4 BRC-349

हमें फॉलो करें: DRMBRCWR • drm_vadodara

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

बाउंड्री वॉल का निर्माण

ई-निविदा सूचना सं.

DRM-BRC 177 OF 2025-26

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मंडल रेल प्रबंधक (W A/C.), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004 द्वारा निम्नानुसार कार्यों हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम:** प्रतापनगर और वडोदरा (P) - उल्लंघन एवं अतिक्रमण की रोकथाम करने के लिए 4.50 कि.मी. लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण। **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में):** 4,56,97,103.81, **जमा कराने की बीड सुरक्षा (₹ में):** 3,78,500.00, **निविदा जमा कराने एवं निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा दिनांक 02/03/2026 को 15:00 बजे से पहले जमा की जाएगी एवं उसी दिनांक को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी। **वेबसाईट का विवरण एवं नोटीस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं एवं कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीद सकते हैं:** वेबसाईट: @ www.ireps.gov.in मंडल रेल प्रबंधक (W A/C), पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4 BRC-353

हमें फॉलो करें: DRMBRCWR • drm_vadodara

राज्य में शीघ्र बड़े पैमाने पर पदों पर भर्ती; नई प्रणाली से होंगी नियुक्तियाँ– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही नई प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्तियाँ की जाएँगी। इसमें महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के साथ-साथ आयोग के बाहर के पद भी शामिल होंगे।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यक कौशल, सेवा में प्रवेश, पात्रता और कार्य की प्रकृति के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन को लेकर सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रशासन के प्रमुख विभागों में व्यापक प्रशासनिक सुधार तेज़ी से लागू किए जाने चाहिए। मानव संसाधन प्रबंधन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन से संबंधित निर्णय शीघ्र ही मंत्रिमंडल बैठक में लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सामान्य प्रशासन विभाग केवल औपचारिक विभाग नहीं है, बल्कि राज्य की पूरी भर्ती व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने से प्रशासन की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत मानव संसाधन प्रबंधन मॉडल को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सराहना मिली है। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने अन्य राज्यों को भी इस सुधार मॉडल को अपनाने के निर्देश दिए थे। इससे प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश के लिए मार्गदर्शक बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक दस्तावेज़ों, लंबी कतारों और देरी से बचने के लिए ऑनलाइन और डिजिटल सत्यापन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि पासपोर्ट जैसे संवेदनशील दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन संभव है, तो यही मॉडल अन्य प्रक्रियाओं में भी अपनाया जा सकता है।

इसके लिए प्रत्येक विभाग को डिजिलॉकर प्रणाली और ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय होनी चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का संदेह, पक्षपात या अन्याय न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रणाली स्वच्छ, सुदृढ़ और भरोसेमंद होनी चाहिए, ताकि युवाओं के मन में कोई शंका न रहे। आने वाले समय में महाराष्ट्र में शासन सुधार का एक नया मॉडल स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय के साथ इन प्रशासनिक सुधारों को सफल बनाने का आह्वान किया।

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में भी भाजपा ने लहराया परचम, एनसीपी ने चौंकाया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत चुनाव में भी जोरदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में बीती 8 फरवरी को जिला परिषद की 731 सीटों और 1462 पंचायत समितियों के लिए मतदान हुआ था। आज उनके नतीजे आ रहे हैं। अभी तक सामने आए नतीजों में भाजपा ने जिला परिषद की 145 सीटों पर बढ़त बना ली है। भाजपा के साथ ही सहयोगी दल शिवसेना ने 85 और अजित पवार की एनसीपी ने 80 सीटों पर बढ़त बना ली है।

जिला परिषद चुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन जारी

भाजपा ने सांगली, सतारा और पनवेल में बढ़त बनाई है। वहीं एनसीपी ने चौंकाते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने गढ़ बारामती में अन्य पार्टियों से काफी आगे है।

बीते दिनों विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी को सहानुभूति की लहर का फायदा मिलता दिख रहा है।

पहले जिला परिषद और पंचायत चुनाव 5 फरवरी को होने थे, लेकिन अजित पवार के निधन के बाद इन्हें 8 फरवरी तक टाल दिया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोल्हापुर यहां पांच सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी और कांग्रेस यहां चार सीटों पर आगे हैं।

लातूर जिले में भाजपा 16 सीटों पर आगे है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, जो 15 सीटों पर आगे है। एनसीपी यहां 10 सीटों पर और शिवसेना दो सीटों पर आगे हैं।

जिला परिषद की 15 सीटों पर एनसीपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस और भाजपा 13-13 सीटों पर आगे हैं। धाराशिव जिला परिषद की 12 सीटों पर शिवसेना आगे हैं। भाजपा यहां 10 सीटों पर आगे है। शिवसेना यूबीटी परभनी जिला परिषद चुनाव में भाजपा, शिवसेना ने अहम सीटों पर जीत दर्ज की है। सांगली जिले में भाजपा 16 सीटों पर आगे है और यहां भाजपा समर्थकों ने जीत की खुशी मनानी शुरू कर दी है।

परीक्षा अवधि में सीसीटीवी रहित केंद्रों पर अन्य विद्यालयों से केंद्र संचालक

मुंबई विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की जानकारी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल के अंतर्गत नकलमुक्त अभियान के तहत कक्षा बारहवीं और दसवीं की परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। मंडल की सचिव ज्योत्सना शिंदे-पवार ने जानकारी दी कि जिन केंद्रों पर कैमरे उपलब्ध नहीं थे, उनकी संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। जिन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ केंद्र संचालक तथा समस्त कर्मचारी अन्य विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों से नियुक्त किए जाएंगे। मुंबई विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र तथा माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र की लिखित परीक्षाएँ निर्धारित अवधि में संपन्न कराई गईं।

मंडल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पहले कुछ परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी न होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद केंद्र संचालकों, पर्यवेक्षकों, शिक्षण अधिकारियों और शिक्षण निरीक्षकों के साथ बैठक कर नकलमुक्त अभियान के अनुरूप सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में अधिकांश केंद्रों पर कैमरे स्थापित हो जाने के कारण, सीसीटीवी रहित केंद्रों की संख्या में कमी आई है, यह जानकारी मुंबई विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल ने दी।

तुर्भे विभाग में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

नवी मुंबई महानगरपालिका के तुर्भे विभाग अंतर्गत सेक्टर, संपाड़ागांव, संपाड़ा, नवी मुंबई में स्थित मकान क्रमांक 518 पर श्री धनपाल गोकुल पाटिल एवं श्रीमती मालती धनपाल पाटिल द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बिना अनुमति के आर.सी.सी. ढांचे में चौथी मंज़िल (ग्राउंड प्लस चार) का निर्माण किया जा रहा था। यह निर्माण लगभग 9.40 मीटर × 5.0 मीटर क्षेत्रफल में अनधिकृत रूप से किया जा रहा था।

उक्त अनधिकृत निर्माण के संबंध में महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर रचना एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद भी संबंधित स्थान पर अनधिकृत निर्माण कार्य जारी पाया गया।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध विशेष अभियान आयोजित किया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा संबंधित अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।

यह अभियान माननीय आयुक्त के आदेशानुसार, माननीय अतिरिक्त आयुक्त राहुल गेठे के मार्गदर्शन में तथा माननीय उप आयुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलास गायकवाड के निर्देशन में, माननीय सहायक आयुक्त तुर्भे विभाग सागर मोरे के नियंत्रण में संपन्न हुआ। इस कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता विनोद आंब्रे सहित तुर्भे विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी तथा अतिक्रमण विभाग के सुरक्षा रक्षक भी तैनात किए गए थे। अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए चार इलेक्ट्रिक हैमर और दस मज़दूरों की सहायता ली गई।

'वंदे मातरम् सुरक्षित तट समृद्ध भारतम्' साइक्लोथॉन के अवसर पर विशेष साक्षात्कार

'दिलखुलास' और 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमों में उप कमांडेंट विजय चाकोड़ से संवाद

मुंबई(संवाददाता)। 'वंदे मातरम् सुरक्षित तट समृद्ध भारतम्' साइक्लोथॉन पहल के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप कमांडेंट विजय चाकोड़ का विशेष साक्षात्कार सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय द्वारा निर्मित लोकप्रिय कार्यक्रम दिलखुलास और जय महाराष्ट्र में प्रसारित किया जाएगा।

इस साइक्लोथॉन पहल के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साइकिल सवारों की एक टीम महाराष्ट्र के तटीय मार्ग से होकर यात्रा करेगी। यह आयोजन 'वंदे मातरम्' गीत की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के नागरिकों में मादक पदार्थों, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और तटीय सुरक्षा के महत्व के प्रति नागरिकों को जागरूक करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। साइक्लोथॉन की राज्य में यात्रा के दौरान तारापुर, गेटवे ऑफ इंडिया, कुरुल, लोनेरे, अंजनवेल और रत्नागिरी में विविध सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद यह टीम अगले चरण की यात्रा के लिए गोवा राज्य के लिए प्रस्थान करेगी। उप कमांडेंट विजय चाकोड़ ने इस पहल की योजना, क्रियान्वयन और संपूर्ण रूपरेखा के बारे में 'दिलखुलास' और 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमों के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी है। यह साक्षात्कार आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा और साथ ही 'न्यूज़ ऑन एआईआर' मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रम के अंतर्गत यह साक्षात्कार सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों पर भी प्रसारित किया जाएगा।

स्वस्थ जीवनशैली के लिए बच्चे और बूढ़ों ने दिखाया दम!

ठाणे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 'ठाणे हाफ मैराथन' का 12वां संस्करण रविवार, (8 फरवरी 2026) को हीरानंदानी एस्टेट, ठाणे के टीएमसी ग्राउंड में आयोजित किया गया। जिसमें लगभग 12 हजार धावकों ने भाग लिया। इस रेस की तीन श्रेणी 21 किमी, 10 किमी और 4 किमी (फन रन) में लोगों ने दौड़ लगाई। 4 किलोमीटर रन में छोटे बच्चो ने भी हिस्सा लिया। स्वस्थ जीवनशैली और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ठाणे हाफ मैराथन एक फ्लैगशिप स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है।

इस रेस के ब्रांड एंबेसडर मिलिंद सोमन ने भी 10 किमी तक दौड़ लगाई। इस मौके पर फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने कहा कि मैं लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना चाहता हूं, इसलिए जो भी मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है उनको कहता हूं पहले आप पुश-अप्स करों फिर सेल्फी लो। आज की तनावपूर्ण ज़िंदगी में बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूकता जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाना बेहद जरुरी है।

इस रेस में दौड़ने वाले यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदेशक आशीष पांडेय ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया हमेशा से ही बैंकिंग क्षेत्र हो या सोसायटी का डेवलपमेंट, हमेशा लोगो की मदद में अग्रसर रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोग स्वस्थ होंगे तब देश स्वस्थ रहेगा और तभी देश विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में और तरक्की करेगा। वहीं, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा तो मानना है कि 'फिट है तो हिट है' आप जितना सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय रुद्रा ने कहा कि हार जीत से ज्यादा जरूरी है कि लोग इस तरह की स्पर्धा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें जो की मुंबईवासियों के लिए बेहद जरूरी है।

इस रेस में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने लोगों में जोश भरते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात ये है कि इस रेस में छोटे बच्चों ने भी दौड़ लगाई, जिसे देखकर लगता है कि लोग फिटनेस को लेकर काफी सचेत हैं।

इस रेस में पुरुष 21 किमी रेस में दाजी हुबले प्रथम, विशाल कंबीरे दूसरे और सूरज ज़ोरे तीसरे नंबर पर रहे। जबकि, महिला 21 किमी रेस में अमृता पटेल प्रथम, प्राजकता गोडबोले दूसरे और मनीषा जोशी तीसरे नंबर पर रही।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून और अधिक सख्त व प्रभावी बनाए जाने चाहिए– उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे

संरक्षण अधिकारियों और भरोसा सेल अधिकारियों की संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों का अधिक प्रभावी और सख्त क्रियान्वयन आवश्यक है, ऐसा विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू हिंसा प्रतिबंध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के संरक्षण अधिकारियों तथा पुलिस विभाग के भरोसा सेल अधिकारियों के बीच जिला, तालुका और क्षेत्र स्तर पर संयुक्त समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँ।

विधान भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में घरेलू हिंसा प्रतिबंध अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने, शक्ति विधेयक के क्रियान्वयन के अनुरूप आगे की दिशा तय करने तथा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने कहा कि यदि पुलिस कार्यप्रणाली में संबंधित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए, तो पीड़ितों को राहत मिल सकती है। इसलिए पुलिस को एक सुव्यवस्थित और संवेदनशील कार्यप्रणाली तैयार करनी चाहिए। साथ ही संबंधित विभागों को इन सभी विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को भेजी जाएगी।

बैठक में पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अश्वती डोरजे, पूर्व न्यायमूर्ति साधना जाधव, महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त नयना गुंडे, उपसचिव डॉ. जयंत सारोडे, विधि व न्याय विभाग के उपसचिव सागर बोंद्रे तथा गृह विभाग के अवर सचिव जयसेन इंगोले उपस्थित थे।

डॉ. गोरहे ने कहा कि महिलाओं के आत्मसम्मान, गरिमा और सुरक्षा के लिए राज्य की सभी एजेंसियों को समन्वित और संवेदनशील तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा की शिकार न हों, इसके लिए निवारक उपायों का अधिक प्रभावी और सख्त क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाना आवश्यक है। पुलिस विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को मिलकर जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। जिला स्तरीय महिला सतर्कता समितियों के कार्य की नियमित समीक्षा कर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने पीड़ित महिलाओं को तत्काल संरक्षण आदेश उपलब्ध कराने, भरण-पोषण की प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचने तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय बढ़ाकर महिलाओं को कानूनी सलाह उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाज की मानसिकता से जुड़ा गंभीर विषय है। इसलिए केवल कानूनों को सख्त बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका क्रियान्वयन पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी होना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण, न्याय और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा समन्वित प्रयास किए जाना समय की आवश्यकता है।

कर्तृत्ववान नेतृत्व का परिणाम : परभणी ज़िले में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता

परभणी। परभणी ज़िले की पालकमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर के सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके प्रभावी नेतृत्व का ही परिणाम है कि ज़िले में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में भाजपा का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ा है और जनता का विश्वास पार्टी के प्रति और अधिक मजबूत हुआ है।

जहाँ पहले परभणी ज़िले में भाजपा का एक भी नगराध्यक्ष नहीं था, वहीं आज दो नगराध्यक्ष कार्यरत हैं।

नगर परिषद सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 42 हो गई है। महानगरपालिका सदस्यों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। ज़िला परिषद सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 24 तक पहुँच गई है। इसके साथ ही पंचायत समिति सदस्यों की संख्या अब 44 हो गई है। यह वृद्धि केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा की नीतियों पर जनता द्वारा जताए गए विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है। ज़िले में विकास कार्यों को गति देना, संगठन को सशक्त करना और कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करना–ये सभी कार्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर ने प्रभावी ढंग से किए हैं। उनके नेतृत्व में परभणी ज़िले में भाजपा को नई ऊर्जा और मजबूती मिली है तथा आने वाले समय में विकास की नई दिशाएँ खुलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार

30 से अधिक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन, यात्रियों को होगा सीधा लाभ

रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 30 से अधिक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है। यह बदलाव 10 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्लेटफॉर्म 1 पर यात्री दबाव कम करना, भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना तथा स्टेशन संचालन को सुचारू बनाना है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म परिवर्तन की लगातार उद्घोषणाएं हो रही हैं। पूछताछ काउंटर एवं सूचना बोर्डों पर पूरी जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही, सोशल मीडिया के माध्यम से भी यात्रियों को सूचित किया जा रहा है।

इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांग यात्रियों को विशेष लाभ होगा।रेल प्रशासन डिस्प्ले बोर्ड, उद्घोषणाओं एवं स्टाफ तैनाती के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

इस परिवर्तन से प्लेटफॉर्म 1 पर भीड़ में काफी कमी आएगी।

यात्रियों से अपील है कि सूचना बोर्डों, उद्घोषणाओं पर ध्यान दें या नजदीकी रेलवे कर्मचारियों से संपर्क करें।

रेलवे ऐप एवं NTES ऐप से भी नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। रेल प्रशासन यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत है।

सम्पादकीय

रूस से तेल या अमेरिका से व्यापार की राह, भारत के नए समझौते की अग्निपरीक्षा

पिछले करीब एक वर्ष से गहन विचार-विमर्श के बाद भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आखिरकार द्विपक्षीय सहमति बन गई है। दोनों देशों की ओर से शनिवार को इसका एलान किया गया। समझौते के नियम-शर्तों के तहत अमेरिका, भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को घटाकर अठारह फीसद करेगा। वहीं, भारत की ओर से अमेरिका की सभी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क समाप्त या कम किया जाएगा।

निश्चित रूप से यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन नफा-नुकसान का पलड़ा किस ओर भारी रहेगा, इसको लेकर अलग-अलग विश्लेषण सामने आए हैं। ऐसे में कुछ आशंकाएं और सवाल भी उठ रहे हैं कि इस समझौते को आकार देने में अड़चन कहां थी और अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्ष इसके लिए राजी हो गए। हालांकि, इस मामले में भारतीय सत्तापक्ष की ओर से स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है।

भारत और अमेरिका ने पिछले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर पहले चरण की बातचीत शुरू की थी। कई दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कुछ मसलों पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिनमें भारतीय कृषि और डेयरी बाजार में अमेरिका की पहुंच को विस्तार देने का मुद्दा भी शामिल था। दरअसल, अमेरिका शुरू से यह मांग करता रहा है कि भारतीय कृषि एवं डेयरी बाजार को उसके लिए पूरी तरह खोल दिया जाए। जबकि भारत इस मांग को खारिज करता रहा है। अब इस समझौते की जिस रूपरेखा पर सहमति बनी है, उसके मुताबिक अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर भारत आयात शुल्क समाप्त या कम करेगा।

इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि भारत ने इस मसले पर उदार रुख अपनाकर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। माना जा रहा है कि समझौते के लागू होने से भारतीय बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पादों की आवक बढ़ेगी, जिसका असर देश के किसानों पर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार का दावा है कि देश के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस समझौते से उन्हें भी लाभ होगा।

व्यापार समझौते की शर्तों में यह बात भी शामिल है कि भारत अगले पांच वर्ष में 500 अरब डालर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान एवं उसके कलपुर्जे, कीमती धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोयला खरीदेगा। साथ ही रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीद बंद करनी होगी। यानी समझौते का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इन शर्तों को पूरा कर पाता है या नहीं। इसमें दोराय नहीं कि भारतीय वस्तुओं का निर्यात, जो अमेरिकी शुल्क की वजह से प्रभावित हुआ था, वह फिर से पटरी लौट आएगा।

सरकार का कहना है कि इससे तीस हजार अरब अमेरिकी डालर का बाजार खुलेगा, जो भारतीय निर्यात को नई दिशा देगा। सवाल है कि क्या अमेरिका से आयात और निर्यात के बीच संतुलन का ध्यान रखा गया है? विपक्ष का आरोप है कि इस समझौते से भारत के मुकाबले अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा।

वहीं सत्तापक्ष की दलील है कि अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों को कोटा-आधारित शुल्क रियायत दी जाएगी, जिसका भारतीय किसानों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल, समझौते के नफा-नुकसान का वास्तविक आकलन तभी हो पाएगा, जब कुछ दिनों में द्विपक्षीय कारोबार के आंकड़े सामने आएंगे।

डील बदली, दिशा बदलीः मोदी युग में भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है

'अब भारत सहमति नहीं माँगता, साझेदारी तय करता है।'

प्रोफ़ेसर डॉ दयानंद तिवारी
प्रवक्ता भाजपा,
मुंबई, महाराष्ट्र

भारत के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक इतिहास में वर्तमान समय केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना में आए युगांतकारी परिवर्तन का साक्षी है। यह वह दौर है जहाँ भारत ने स्वयं को देखने का नज़रिया बदला है–और दुनिया ने भारत को देखने का तरीका।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज जिस आत्मविश्वास, स्पष्टता और निर्णायकता के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा है, वह किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। यह वर्षों की नीतिगत स्पष्टता, रणनीतिक धैर्य और राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखने वाली सोच की परिणति है।

हालिया भारत-अमेरिका व्यापार और रणनीतिक निर्णय इस बदले हुए भारत की पुष्टि करते हैं। यह निर्णय केवल आर्थिक लेन-देन नहीं, बल्कि इस सच्चाई की वैश्विक स्वीकृति है कि भारत अब दबाव में नहीं, अपनी शर्तों पर निर्णय लेता है।

मोदी सरकारः जहाँ नीति स्पष्ट है और नीयत राष्ट्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति–दोनों का मूल आधार एक ही हैः राष्ट्रीय स्वाभिमान।

चाहे वह–

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो,

डिजिटल अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेतृत्व, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की निर्णायक भूमिका,

या फिर व्यापार समझौतों में स्पष्ट 'रेड लाइन्स'– हर जगह भारत यह संदेश देता है कि राष्ट्रहित पर कोई समझौता नहीं होगा।

यही कारण है कि आज भारत न तो किसी की अनुकंपा पर निर्भर है और न ही किसी वैश्विक शक्ति की शर्तों पर चलने को विवश।

भारत आज बराबरी की भाषा बोलता है–और दुनिया उसे गंभीरता से सुनती है।

2047 का भारतः सपना नहीं, सुविचारित रणनीति

2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाना कोई भावनात्मक नारा नहीं है। यह एक डेटा-आधारित, नीति-प्रेरित और लक्ष्य-केंद्रित रोडमैप है।

आज भारत–

दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, वैश्विक आपूर्ति शृंखला का भरोसेमंद केंद्र बन रहा है, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप इकोसिस्टम, फार्मा, आईटी और अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

ये उपलब्धियाँ उस भारत की झलक हैं, जो आने वाले वर्षों में केवल बाज़ार नहीं, बल्कि नीति-निर्माता और दिशा-निर्देशक बनेगा।

आज की नीतियाँ, कल के भारत की नींव

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया–ये केवल सरकारी योजनाएँ नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की आधारशिलाएँ हैं।

मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह–

अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित है,

किसानों, श्रमिकों, युवाओं और उद्योगों के हितों से समझौता किए बिना वैश्विक समझौतों में भागीदारी करती है। यही कारण है कि भारत आज आर्थिक शक्ति के साथ-साथ नैतिक और रणनीतिक शक्ति भी बनकर उभरा है।

अमेरिकी निर्णय और भारतीय आत्मविश्वास

अमेरिका से जुड़े हालिया निर्णय पर देश के आम नागरिक को गर्व है। यह गर्व किसी एक सरकार का नहीं, बल्कि भारतीय होने की सामूहिक भावना का है।

देश आज यह महसूस कर रहा है कि–

'भारत को अब नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।'

यह सफलता बिना शोर, बिना धमकी और बिना टकराव के हासिल की गई। संयम, तर्क और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात मनवाना–यही भारतीय कूटनीति की पहचान है। शक्ति के साथ शांति–यही नया भारत है। विपक्ष को आत्ममंथन की आवश्यकता

ऐसे ऐतिहासिक क्षण में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए?

जब देश वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मज़बूत कर रहा हो, तब संसद के भीतर–

बार-बार व्यवधान, अनावश्यक शोर, और लोकतांत्रिक समय की बर्बादी– राष्ट्रहित के विरुद्ध जाती है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, राजनीतिक प्रदर्शन का मंच नहीं।

आलोचना लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, लेकिन अवरोध लोकतंत्र को कमजोर करता है।

भारत अब अनुमति नहीं, साझेदारी चाहता है मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि मूलतः बदल चुकी है। भारत अब– अनुमति नहीं माँगता, बराबरी पर साझेदारी करता है, और साझा हितों पर निर्णय लेता है।

यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत को केवल एक बाज़ार नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखते हैं।

यह परिवर्तन कूटनीति से आगे बढ़कर 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है।

नया भारतः निर्णायक, आत्मनिर्भर और नेतृत्वकर्ता

आज का भारत– निर्णय लेता है, दिशा तय करता है, और परिणाम लाता है। 2047 का भारत कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज की नीतियों का स्वाभाविक परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि– राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उसी कसौटी पर हर वैश्विक समझौता, हर नीति और हर निर्णय होगा।

भारत अब पीछे चलने वाला देश नहीं रहा। भारत अब नेतृत्व करता है। और दुनिया–इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है।

जय हिंद

स्कूलों में शौचालय और माहवारी स्वच्छता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पर जमीनी हकीकत अब भी चिंताजनक

सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज का मजबूत आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) ने इसे परिवर्तित, सुधारे गए और अधिक सक्षम बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। चाहे सरकार द्वारा संचालित स्कूल हों या निजी संस्थान, शिक्षा सब तक समान रूप से पहुंचनी चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति एक जैसी होनी चाहिए। अगर शिक्षा प्रणाली और प्रबंधन में एकरूपता आ जाए, तो वर्ग-भेद मिट जाएंगे। शिक्षा के मंदिरों का स्वरूप भी लगभग एक समान होना चाहिए। निजी विद्यालयों पर नियमों की भरमार हो और सरकारी स्कूलों में उनकी अनदेखी हो, यह स्वीकार्य नहीं। अगर निजी स्कूल संसाधनों या नियमों के अभाव में कमजोर पड़ते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसी प्रकार, सरकारी विद्यालयों में नियमों की अवहेलना पर उनकी मान्यता रद्द करने का प्रावधान अनिवार्य होना चाहिए।

एनईपी-2020 शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक और योजनाबद्ध तरीके का भरोसा दिलाती है। पांच वर्ष बीतने के बावजूद इसके उज्ज्वल परिणाम अभी देखना शेष है, लेकिन यह स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और हितधारकों को सशक्त बनाने तथा संसाधनों से परिपूर्ण रखने वाली संस्कृति विकसित करने का वादा करती है। साथ ही, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण पर जोर दिया गया है। शिक्षा संस्थानों में उपयोगी संसाधनों का समुचित उपयोग सभी को लाभान्वित करता है। स्कूल प्रबंधन में खेलकूद के साधन, कक्षाओं की उपलब्धता और स्थानीय नागरिकों का जुड़ाव शिक्षा व्यवस्था को ऊर्जावान बनाता है। मगर बच्चों के लिए आवश्यक संसाधनों के अभाव में बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या बनी रहती है। विशेष रूप से छात्राओं के लिए स्कूल समय के दौरान निजी जरूरतों की व्यवस्था पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।

भारत जैसे विकासशील देश के अधिकांश स्कूलों में- चाहे वे केंद्र या राज्य सरकार के हों या निजी- छात्राओं के लिए पर्याप्त शौचालयों का अभाव है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की मूलभूत सुविधाओं का न होना छात्राओं को शिक्षा से दूर कर देता है। अगर शौचालयों के साथ-साथ सैनिटरी पैड और माहवारी स्वच्छता के मौलिक अधिकार पर ध्यान न दिया जाए, तो छात्राओं की स्कूल से दूरी बढ़ती जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सैनिटरी पैड मशीनें लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद खराब होने पर ये सरकार की प्राथमिकता सूची से बाहर हो जाती हैं। अनेक मामलों में शौचालय ताले में बंद रहते हैं, जिससे छात्राओं को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि सामाजिक कुप्रथा को भी बढ़ावा देता है।

विचित्र है कि भारत में ऐसे जरूरी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों को सक्रिय होना पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रबंधन शिक्षा-शास्त्रियों और उच्च वेतनभोगी नौकरशाहों की सोच का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता? सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण अनिवार्य किया है, ताकि छात्राएं अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकें। यह सुविधा मध्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। फिर भी, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कमजोर है।

सरकार को प्रत्येक स्कूल में छात्राओं को जैविक रूप से अपघटनीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने चाहिए। स्कूल प्रबंधन सरकारी हो या गैर-सरकारी, अगर शौचालय या स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता है, तो उनकी जवाबदेही तय करते हुए मान्यता रद्द की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रबंधन के दृष्टिकोण से इसके मसविदे पर पुनर्विचार आवश्यक है। छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता को नीति का प्रभावी हिस्सा बनाना होगा।

नई शिक्षा नीति- 2020 ने स्कूलों को संसाधन-संपन्न बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा किया है, लेकिन छात्राओं की इन बुनियादी जरूरतों पर ठोस प्रावधानों का अभाव है। अगर इस संवेदनशील विषय पर ध्यान न दिया गया, तो बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही लिंग भेदभाव गहरा जाएगा। छात्राएं शिक्षा से वंचित रहेंगी, जो राष्ट्र निर्माण के लिए घातक होगा। सरकार, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में छात्राओं के लिए अलग, स्वच्छ और कार्यशील शौचालय अनिवार्य किए जाने की जरूरत है।

अनेक अध्ययनों में यह तथ्य उजागर हो चुका है कि स्वच्छ शौचालय और पेयजल के अभाव के कारण बहुत सारी लड़कियां अपनी स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसके अलावा, माहवारी से जुड़ी परेशानियों को लेकर भी समाज में लोग सहज नहीं होते और इसका खमियाजा महिलाओं और लड़कियों को उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जैविक रूप से अपघटनीय सैनिटरी पैड स्कूल प्रबंधन द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मशीनों के रखरखाव के लिए नियमित निगरानी और कोष सुनिश्चित करने की जरूरत है। मान्यता रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। जागरूकता अभियान चलाकर मासिक धर्म को संकीर्ण सोच से मुक्त किए जाने की जरूरत है। यदि एनईपी को इन मुद्दों से समृद्ध किया जाए, तो यह वास्तव में समावेशी और सशक्तीकरण लाने वाली बनेगी। आधी आबादी को शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए अब ठोस कार्रवाई जरूरी है।

ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ पूरा जोर लगाकर दुनिया को चिंता में डाला

ईरान पर युद्ध के मंडराते बादल अब और घने होते जा रहे हैं क्योंकि ओमान में बातचीत के लिए आये ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर बातचीत नहीं की। बातचीत ओमान की मध्यस्थता में हुई। यानि ईरान अपनी बात ओमान से कहता, ओमान वही बात जाकर अमेरिका से कहता और अमेरिकी जवाब को आकर ईरानी प्रतिनिधि को बताता। साथ ही इस वार्ता से पहले दोनों ओर से जिस तरह के धमकी भरे बयान आये और भारी हथियारों की तैनाती की गयी उससे यह साफ हो चला था कि वार्ता महज दिखावा है।

हम आपको बता दें कि ओमान ने कहा है कि उसके विदेश मंत्री ने मस्कट में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों से अलग अलग मुलाकात कर परमाणु मामले पर परोक्ष वार्ता को आगे बढ़ाया। बताया जा रहा है कि वार्ता स्थल पर ईरान इस बात से भड़क गया कि अमेरिकी दल में एडमिरल ब्रैड कूपर जैसे सैन्य अधिकारी मौजूद थे। देखा जाये तो बीते वर्ष ईरान के परमाणु ढांचे पर हुए अमेरिकी हमले के बाद भले पहली औपचारिक वार्ता हुई लेकिन उससे पहले ही बयानबाजी, सैन्य जमावड़े और परोक्ष धमकियों ने माहौल को बारूदी बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को खुली चेतावनी दी कि उन्हें बहुत चिंतित रहना चाहिए। यह चेतावनी उस समय आयी है जब ईरान के भीतर सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई हुई, इंटरनेट पर पाबंदी लगी और सड़कों पर असंतोष उभरा।

हम आपको बता दें कि ओमान की राजधानी मस्कट में हुई वार्ता में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेड कुश्नर शामिल हुए। वार्ता शुरू होने से पहले भी अनिश्चितता बनी रही। खबरें आयीं कि आधिकारिक शुरुआत टली हुई है लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि संदेश ओमान के जरिये आगे पीछे किये जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने वार्ता से पहले कहा था कि वह चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को समर्थन और अपने नागरिकों के साथ ईरान के व्यवहार पर भी चर्चा हो मगर तेहरान ने साफ कह दिया था कि बात केवल परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने तक सीमित रहेगी।

ईरान ने संकेत दिये हैं कि वह यूरेनियम संवर्धन पर कुछ लचीलापन दिखा सकता है, यहां तक कि उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम का कुछ भंडार सौंपने या साझा व्यवस्था के तहत शून्य संवर्धन तक पर विचार कर सकता है। पर साथ ही वह कहता है कि संवर्धन का अधिकार सौदे का विषय नहीं और 2018 के बाद फिर लगाये गये प्रतिबंध हटने चाहिए।

इसी बीच, ईरानी सरकारी प्रसारण ने बताया कि उसकी सबसे उन्नत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर चार को भूमिगत मिसाइल नगर में तैनात किया गया है। इसकी मारक दूरी 1240 मील से अधिक और भारी वारहेड ढोने की क्षमता बतायी गयी है। इस दौरान ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के राजनीतिक उप प्रमुख यदोल्लाह जवानी ने दो टूक कहा कि कूटनीति अपनाने का अर्थ सैन्य ताकत छोड़ना नहीं है, ईरान युद्ध नहीं चाहता पर यदि दूसरी ओर से गलती हुई तो जवाब निर्णायक होगा। यह सब उस समय हुआ जब ट्रंप प्रशासन ने हाल के सप्ताहों में पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और साधन बढ़ाये हैं, जिससे साफ है कि वार्ता की मेज के नीचे भी दबाव की राजनीति पूरी ताकत से चल रही है।

ईरान समुद्री मोर्चे पर सीधी बराबरी की जगह अपनी युद्ध नीति पर भरोसा करता है। उसका लक्ष्य है कि खाड़ी का जलक्षेत्र इतना जोखिम भरा बना दिया जाये कि किसी भी अमेरिकी विमान वाहक पोत के लिए वहां ठहरना महंगा सौदा लगे। ईरान जानता है कि जहाज दर जहाज मुकाबला उसके बस की बात नहीं, इसलिए वह सस्ते और असरदार हथियार, तेज नौकाएं, मानवरहित यान और तंग जलमार्ग का सहारा लेकर महंगे दुश्मन साधनों को निशाना बनाने की सोच रखता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य अपने सबसे संकरे हिस्से में बहुत कम चौड़ा है, जहां बड़े पोतों की चाल सीमित हो जाती है और वे अनुमानित रास्तों पर चलने को मजबूर होते हैं। उत्तरी तट पर पकड़ रखने वाला ईरान जमीन से मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र और तटीय ठिकानों से ऐसे पोतों को आसानी से साध सकता है।

रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के पास सैकड़ों छोटी और तेज आक्रमण नौकाएं हैं जिन पर मशीनगन, राकेट और टारपीडो लगे रहते हैं। ये नौकाएं झुंड की नीति अपनाती हैं, यानी एक ही बड़े पोत पर कई दिशाओं से एक साथ धावा। पारंपरिक रक्षा तंत्र दूर से आते प्रक्षेपास्त्र रोकने में सक्षम हो सकता है, पर एक साथ आती अनेक छोटी नौकाओं और मानवरहित यानों पर नजर रखना कठिन हो जाता है। ईरान ने समुद्र में चलते जहाजों को साधने वाले खास प्रक्षेपास्त्र भी विकसित किये हैं जिनकी मारक दूरी सैकड़ों किलोमीटर बतायी जाती है और जिनकी रफ्तार बहुत तेज कही जाती है। कम कीमत वाले शाहेद जैसे मानवरहित यान बड़ी संख्या में भेजे जाएं तो वे रक्षा कवच पर दबाव डालते हैं, और भले ही कई गिरा दिये जाएं, लागत का अंतर ईरान के पक्ष में रहता है।

इसके साथ ही गदीर श्रेणी की छोटी पनडुब्बियां उथले पानी के लिए ढाली गयी हैं। ये समुद्र तल के पास छिपकर घात लगा सकती हैं और भारी टारपीडो से बड़े युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। समुद्री बारूदी सुरंगें भी ईरान के शस्त्रागार का अहम हिस्सा हैं; संकरे जलमार्ग में एक सुरंग भी बहुमूल्य पोत को लंबे समय के लिए निष्क्रिय कर सकती है। हाल में फत्ताह दो जैसे अति तीव्र गति वाले प्रक्षेपास्त्र के दावे भी किये गये, जिन्हें रोकना कठिन बताया जाता है। ईरान की सोच साफ हैः दुश्मन के एक महंगे पोत की कीमत में वह अनेक हमले कर सकता है। 2002 के एक अमेरिकी सैन्य अभ्यास में भी दिखा था कि झुंड नीति और अनोखे तरीके भारी तकनीक पर भारी पड़ सकते हैं। यही भरोसा तेहरान को टकराव की स्थिति में मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है।

दूसरी ओर ट्रंप का दावा है कि पिछले हमलों से ईरान के परमाणु ढांचे का पूर्ण विनाश हुआ और इसी से पश्चिम एशिया में शांति बनी रही। उनका कहना है कि यदि हमला न होता तो अरब देश कभी निश्चिंत नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान नये स्थलों पर कार्यक्रम फिर शुरू करने की सोच रहा था, जिसे अमेरिका ने पहले ही भांप लिया और सख्त चेतावनी दी। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पहले ही कह दिया था कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बैठक के लिए तैयार हैं और अमेरिका संवाद चाहता है, हालांकि समझौते को लेकर भरोसा पक्का नहीं है।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच तनाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। अरब सागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत ने अपने पास आये एक ईरानी मानवरहित विमान को मार गिराया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौकाओं ने अमेरिकी झंडा लगे तेल वाहक जहाज के पास जाकर उसे रोकने की धमकी दी थी। हम आपको बता दें कि यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसलिए यहां जरा-सी चिंगारी भी वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला सकती है।

इस बीच, अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। कहा गया है कि सरकारी मदद पर निर्भर न रहें, वैकल्पिक संपर्क साधन रखें, सड़कों पर प्रदर्शनों से दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर खाद्य, जल और दवाओं का भंडार रखें। दोहरी नागरिकता वालों को ईरानी यात्रा दस्तावेज से निकलने की सलाह दी गयी है। देखा जाये तो क्षेत्रीय परिदृश्य बदल चुका है। गाजा संघर्ष के बाद और सीरिया में बशर अल असद के पतन से तेहरान के कई क्षेत्रीय साथी कमजोर पड़े हैं। इजराइली नेतृत्व ईरान की मिसाइल और परमाणु महत्वाकांक्षा को दोहरी बीमारी बताता रहा है। ऐसे में वार्ता केवल दो देशों की नहीं, पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकती है।

अब सवाल है कि ओमान को ही वार्ता के लिए क्यों चुना गया? दरअसल ओमान लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ रहा है। उसने पहले भी गुप्त और खुली बातचीत के लिए शांत मंच दिया। वह खाड़ी का ऐसा देश है जो टकराव से दूरी रखता है, सब पक्षों से बात करता है और सुरक्षा के साथ गोपनीयता भी देता है। मस्कट भौगोलिक रूप से नजदीक है, समुद्री पहुंच सरल है और वहां बातचीत बिना शोर के हो सकती है। तेहरान को वहां सम्मानजनक माहौल मिलता है और वाशिंगटन को तटस्थ पुल। यही कारण है कि जब सीधे संवाद कठिन हों, तो रास्ता मस्कट से होकर जाता है।

मनोविज्ञानशाला उप्र प्रयागराज की ओर से विद्यालयी शिक्षा में निर्देशन, परामर्श विषयक संगोष्ठी संपन्न

विद्यालय से बच्चों का होता है चतुर्दिक विकास : भगवती सिंह

शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देशन, परामर्श की सेवाएं देते रहे : पीएन सिंह

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से विद्यालयी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श विषयक एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन आज किया गया। शुभारम्भ उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज (यूपी बोर्ड) के सचिव भगवती सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। सचिव

भगवती सिंह ने कहा कि निर्देशन केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो ना केवल विद्यार्थी से जुड़ी होती है, बल्कि शिक्षक, अभिभावक तथा संपूर्ण शिक्षा जगत की सामूहिक जिम्मेदारी भी हैविद्यालय न केवल शैक्षणिक विकास में बल्कि बच्चों और किशोरों के मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा सामाजिक कल्याण के निर्माण में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सचिव भगवती सिंह ने कहा कि विद्यालय व्यक्तित्व विकास, मूल्यों के निर्माण, सामाजिक अंतःक्रिया तथा भावनात्मक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। उन्होने कहा कि हाल के वर्षों में विद्यालय जाने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, शैक्षणिक तनाव, नशीले पदार्थों के सेवन, व्यवहार संबंधी कठिनाइयों, सामाजिक कौशल की कमी, साथियों के दबाव तथा आत्मघाती प्रवृत्तियों से जुड़ी बढ़ती चिंताओं ने शैक्षणिक संस्थानों में मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

कार्यक्रम में निदेशक, मनोविज्ञानशाला / डीआईओएस पीएन सिंह ने विद्यालयों में मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएँ विद्यार्थियों को विकासात्मक चुनौतियों से निपटने, लचीलापन विकसित करने, आत्मसम्मान बढ़ाने, निर्णय-निर्माण क्षमताओं में सुधार करने तथा व्यक्तिगत, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्वस्थ समायोजन को प्रोत्साहित करने में सहायक होती हैं।

निदेशक, मनोविज्ञानशाला / डीआईओएस पीएन सिंह ने

भावनात्मक एवं व्यवहारिक समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम तथा सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के संवर्धन में भी योगदान देती हैं। उन्होने कहा कि शिक्षकों, परामर्शदाताओं, अभिभावकों और नीति-निर्माताओं को मिलकर एक सहायक एवं समावेशी विद्यालय वातावरण के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए, जो विद्यार्थियों के समग्र विकास को पोषित करे और उनके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

निदेशक, मनोविज्ञानशाला / डीआईओएस पीएन सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के समस्त प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से निर्देशन एवं परामर्श की सेवाएं सुलभ कराना सुनिश्चित करें।

संगोष्ठी में प्रो एच एस अस्थाना मनोविज्ञान विभाग बीएचयू, विशिष्ट अतिथि प्रो (डा) दिनेश पांडे निदेशक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मंगलायतन विवि अलीगढ़, प्रो संजय कु एवं डॉ जय सिंह मनोविज्ञान विभाग इविवि प्रयागराज, डॉ मुक्ति खेतान राष्ट्रीय और संचारी रोग कार्य कार्यान्वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर।

संगोष्ठी में 120 प्रतिभागियों ने रिसर्च स्कॉलर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभिन्न संस्थाओं से आए हुए छात्र एवं छात्राएं ने शोधपत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान संस्थान के प्रवक्ताओं ने प्रतिभाग किया।

विधायक व सांसद के लिए उनके क्षेत्र में हो स्थाई कार्यालय की व्यवस्था-अमर पाल मौर्य

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। राज्य सभा सांसद अमरपाल मौर्य ने सदन में विधायक के लिए उनके विधानसभा सांसद के लिए लोकसभा क्षेत्र में तथा राज्यसभा सांसद और एलएलसी के लिए उनके नोडल क्षेत्र में स्थाई कार्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। जिला मीडिया प्रभारी भाजपा गंगापार उमेश तिवारी के अनुसार सोमवार को राज्य सभा में बोलते हुए राज्य सभा सांसद और भाजपा काशी क्षेत्र प्रभारी अमर पाल मौर्य ने कहा कि देश में कुल 788 सांसद और 4549 विधायक है जहां एक तरफ ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सरकारी कार्यालय की व्यवस्था है पर विधायक और सांसद के लिए कोई स्थाई

कार्यालय उपलब्ध नहीं है जबकि एक सांसद या विधायक का दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र की जनता से नियमित संवाद करें उनकी समस्याओं को सुने और और समाधान की दिशा में काम करें लेकिन कार्यालय उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य बाधित होता है आम जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से जनसंवाद स्थापित करने में कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। जबकि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद है लोकतंत्र का मूल आधार है कार्यालय न होने से गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती।इसलिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाय जिसके अंतर्गत सभी विधायकों और सांसदों को उनके विधानसभा लोकसभा के जिला विकास खंड तथा तहसील स्तर पर एक स्थाई कार्यालय उपलब्ध कराया जाय तथा कार्यालय के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर/ सहायक की नियुक्ति भी की जाय और उन्हें अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराया जाय तथा सांसद का कार्यालय लोकसभा स्पीकर तथा विधायक का कार्यालय विधानसभा स्पीकर के माध्यम से संचालित किया जाय।

नगर आयुक्त ने स्वच्छ संरक्षण पर विभागीय बैठक आयोजित की

शहर को स्वच्छ करने के लिए सुझाव दिए

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। नगर निगम प्रयागराज ने आज नगर आयुक्त श्री सीलम साई तेजा जी ने स्वच्छ संरक्षण पर विभागीय बैठक आयोजित किया जिसमें

बैठक का उद्देश्य स्वच्छ संरक्षण के महत्व पर चर्चा करना और कार्यों की योजना बनाई गई। बैठक में शामिल होने वाले लोगों में अपर नगर आयुक्त सहायक नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी को शहर में जिसमें सामुदायिक केंद्र, स्कूल, स्थानीय पार्क, शहर के मंदिरों, सड़कों आदि स्थानों पर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा।

बैठक के दौरान चर्चा किए गए कार्यों की एक योजना बनाएं और उन्हें लागू करने के साथ स्वच्छ संरक्षण के तहत स्थानीय स्वच्छता समस्याओं की पहचान स्वच्छता अभियान , कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग पर कार्य करने के निर्देश दिए।

शहर में आगामी बरसात के मौसम से पहले शहर के साथ नगर निगम के समस्त जोनल अधिकारियों को सफाई, चोक

नाली, पुलिया एवं नालों के साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था में सुधार के साथ मरम्मत एवं निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जल निगम के सभी जोन को निर्देश दिए कि नलकूप के मरम्मत एवं पानी को स्वच्छता पर ध्यान देने एवं जल की समस्याओं निस्तारण की बात कही इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त अरविन्द कुमार रॉय, राजीव कुमार शुक्ला जलकल विभाग के महाप्रबंधक गौरव कुमार एवं शिवम मिश्रा सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पाण्डेय मुख्य अभियंता अनिल कुमार मौर्या, दिनेश सचान विद्युत से संजय कटियार एवं सभी जोनल अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मकान पर पुलिस का छापा, भागे युवक-युवतियां

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। सिविल लाइंस के पत्रिका चौराहे के समीप सोमवार शाम पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी की। हालांकि, पुलिस टीम को देखते ही आधा दर्जन से अधिक युवक-युवतियां आसपास की छतों पर कूदकर भाग निकले। पुलिस चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस की छापेमारी और छत से भागते लोगों की फोटो व वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार इसकी पुष्टि नहीं करता है। पुलिस के अनुसार, मोहल्ले के कुछ लोगों ने सोमवार शाम डायल 112 पर फोन कर मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी थी।

इसकी जानकारी होते ही पीआरवी की टीम ने मकान पर दबिश दी। लेकिन, पुलिस की भनक लगते ही मकान के अंदर से आधा दर्जन से अधिक युवक व युवतियां आसपास के मकानों की छत से होते हुए फरार हो गए। पुलिस चार लोगों को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने ले गई।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छत से भागते हुए एक गार्ड को पकड़कर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती दिख रही है। वहीं, कुछ युवक व युवतियों के छतों को फांदते हुए भागने की फोटो दिख रही है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट व रंगदारी

तमाशबीन बने रहे लोग, मंदबुद्धि महिला ने किया विरोध

मंत्र भारत संवाददाता

नैनी, प्रयागराज। नैनी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में दबंगों द्वारा सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों ने रेस्टोरेंट में घुसकर संचालक से मारपीट की, गाली-गलौज की और रंगदारी की मांग की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक राजेश तिवारी ने बताया कि वह कई वर्षों से स्टेशन के सामने रेस्टोरेंट चला रहे हैं। 8 फरवरी की रात करीब 10:35 बजे कुलदीप मिश्रा और अनिल भारतीय अपने 10-12 साथियों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे। खाना खाने के बाद जब उनसे बिल मांगा गया, तो वे गाली-गलौज करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने खुलेआम धमकी दी कि दोबारा पैसे मांगे तो गोली मार देंगे। उन्होंने 2, 000 रुपये प्रति सप्ताह रंगदारी की मांग करते हुए कहा कि पैसे न देने पर रेस्टोरेंट नहीं चलने देंगे और जान से मार देंगे। घटना के दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद अधिकांश लोग मूकदर्शक बने रहे। हालांकि, वहां मौजूद एक मंदबुद्धि महिला ने साहस दिखाते हुए आरोपियों का विरोध किया और उन्हें रोकने का प्रयास किया।

काफी देर बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद राकेश जायसवाल ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया और पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया।

राजेश तिवारी का यह भी आरोप है कि दबंगों ने पुलिस में शिकायत करने पर झूठे एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी, जिससे उनका परिवार मानसिक तनाव में है। पीड़ित ने नैनी थाने में लिखित शिकायत देकर सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दी है। इस संबंध में एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है और जांच की जा रही है।

चार दिन से लापता सिक्योरिटी सुपरवाइजर का शव नैनी में मिला, कर्ज बना मौत की वजह

मंत्र भारत संवाददाता

नैनी, प्रयागराज। कौंधियारा थाना क्षेत्र निवासी राकेश मिश्रा (38) का शव चार दिन बाद नैनी लेप्रोसी चौराहे के पास रेलवे ओवरब्रिज के समीप एक पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारकर स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

मृतक राकेश मिश्रा उर्फ गुड्डू नैनी स्थित गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इकाई में एक सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। वह 5 फरवरी को ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद लापता हो गए थे। परिजनों ने नैनी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान गंगा प्रदूषण बोर्ड परिसर में उनकी बाइक मिली, जिसकी डिग्गी से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। नोट में आत्महत्या करने की बात लिखी थी और करीब 57 लाख रुपये के लेन-देन का उल्लेख था। इसके बाद पुलिस ने यमुना नदी में गोताखोरों की मदद से भी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था।

ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, राकेश पर भारी कर्ज था। बताया जा रहा है कि वह मोबाइल गेम खेलने का आदी था और इसमें पैसे लगाने के कारण उसने ब्याज पर काफी रकम उधार ली थी। कर्जदाताओं के लगातार दबाव के चलते वह मानसिक तनाव में था। बताया गया है कि उस पर करीब 60 लाख रुपये तक का कर्ज हो चुका था।

रविवार रात को राकेश ने

प्रयागराज पहुंचकर नए मोबाइल से अपने साथी राजा से संपर्क किया था और परिवार की जानकारी ली थी। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि युवक ने फांसी लगा ली है।

परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पत्नी ने चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राकेश मोबाइल गेम के कारण कर्ज में डूब गया था और कर्जदाताओं के दबाव से परेशान था। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

'एरी सखी मंगल गाओ री' के सुरों से सजी 'चलो मन गंगा-यमुना तीर' की सांस्कृतिक संध्या

एस. मंगलामुखी ने कथक नृत्य से दर्शकों को किया अभिभूत

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'चलो मन गंगा-यमुना तीर' कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार की सांस्कृतिक संध्या भजन गायक किशोर चतुर्वेदी एवं सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना देवेन्द्र देविका एस. मंगलामुखी की मनोहारी प्रस्तुतियों के नाम रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सशक्त बिरहा से हुआ। इसके पश्चात कथक नृत्यांगना देवेन्द्र देविका एस. मंगलामुखी ने गंगा जी के आह्वान के साथ लखनऊ घराने के झपका कथक की प्रस्तुति देकर दर्शकों को तालियों से मंच को गूंजाने पर विवश कर दिया। उन्होंने शिव रुद्राष्टकम्, पारंपरिक तीन ताल में उपज, ठाठ, विलंबित, टुकड़े, तिहाई एवं सवाल-जवाब की सशक्त प्रस्तुति दी। अभिनय पक्ष में पंडित बिंदादिन महाराज जी की प्रसिद्ध ठुमरी 'डगर चलत' को कथक के माध्यम से भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया।

इसके उपरांत भजन गायक किशोर चतुर्वेदी ने चलो मन गंगा-यमुना तीर, ए री सखी मंगल गाओ री एवं भला हुआ मेरी मटकी फूटी जैसे लोकप्रिय भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं स्वाति रिज़वी ने सबसे ऊंची प्रेम सगाई तथा गंगा मैया में जब तक के पानी रहे की प्रस्तुति देकर श्रोताओं से खूब तालियां बटोरीं। आराधना विश्वकर्मा ने उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुति दी।

इसके बाद प्रत्युष श्रीवास्तव ने जलतरंग व भजन गायन के माध्यम से सांवली सूरत पे मोहन, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं तथा छाप तिलक की जोरदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर राजकुमार, हारमोनियम पर संतोष तिवारी एवं वाद्य यंत्रों पर ज्योति प्रकाश शुक्ल ने संगत की। वहीं संगम क्षेत्र में मान सिंह एवं दल द्वारा स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय शिल्प मेला के अंतर्गत आयोजित नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता तथा ब्रह्मनाद कला महोत्सव के तहत मंत्रोच्चारण, काव्यपाठ, वादन, गायन, नृत्य, चित्रकला एवं मृत्तिकला प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना) को केंद्र निदेशक श्री सुदेश शर्मा, कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय एवं उपनिदेशक डॉ. मुकेश उपाध्याय द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

गंगा समग्र के राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख बनाए गए अखिलेश शर्मा

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने महासचिव अखिलेश शर्मा का बार में किया स्वागत, अभिनंदन

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार शर्मा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन गंगा समग्र का राष्ट्रीय सह सम्पर्क प्रमुख का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें यह दायित्व नई दिल्ली स्थित केआईआईटी वर्ल्ड स्कूल में आयोजित गंगा समग्र के छठवें तीन दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सौंपा गया। कार्यक्रम 6, 7 एवं 8 फरवरी को आयोजित हुआ था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डा कृष्ण गोपाल ने किया। जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे कार्यकर्ताओं को सह सरकार्यवाह डा कृष्ण गोपाल ने संबोधित किया। दूसरे दिन सर्व सम्मति से नौ प्रस्ताव पारित किए गए। तीन दिन तक विभिन्न सत्रों के आयोजन के कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। इस मौके पर मंगल धाम देवघर के संत आचार्य प्रदीप, गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, संयुक्त महामंत्री अवधेश, राष्ट्रीय महामंत्री डॉ आशीष गौतम, केआईआईटी वर्ल्ड स्कूल दिल्ली की प्रधानाचार्य डॉ संगीता भाटिया आदि उपस्थित रहे। महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा को राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख बनाए जाने पर सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पाण्डे बबुआ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार द्विवेदी, उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह, राज कुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र, बैरिस्टर सिंह, रामेश्वर दत्त पाण्डेय, अंजनी कुमार मिश्र, दिवांशु तिवारी, बलदेव शुक्ल, अभिषेक तिवारी, गया प्रसाद मिश्र, गिरीश चन्द्र शुक्ला, अवनीश चन्द्र त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पाण्डेय आदि ने बधाई दी है।

जी ने किया मारुति सुज़ुकी प्रस्तुत 24वें ज़ी सिने अवॉर्ड्स 2026 का ऐलान

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जी, जो भारत की एक बड़ी कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी है, देश के एंटरटेनमेंट जगत को आकार देने में लंबे समय से अहम भूमिका निभाता आया है। ज़ी ने हमेशा कहानियों को नए अंदाज़ में पेश करने की कोशिश की है, ताकि दर्शक उन्हें सिर्फ़ देखें ही नहीं, बल्कि महसूस भी कर सकें। भावनाओं से जुड़ी कहानियों को नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए, ज़ी टीवी, डिजिटल और अलग-अलग भाषाओं में दर्शकों तक पहुंचता रहा है। कई दशकों के अनुभव के साथ, यह नेटवर्क अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दर्शकों से जुड़ने के नए तरीके तलाशता रहा है, जिससे रिश्ता और भी गहरा और मज़बूत बन सके।

स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई

मंत्र भारत संवाददाता

थरवई। स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, 40 नंबर गोमती में कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं के सम्मान में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और भावनाओं से सराबोर रहा। विद्यार्थियों ने विद्यालय और शिक्षकों के प्रति अपने अनुभव साझा किया गया विद्यार्थियों ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान मंदिर है जहाँ से उनके उज्ज्वल भविष्य और करियर की नींव पड़ी। उन्होंने विद्यालय द्वारा दिए गए संस्कारों को जीवनभर का मार्गदर्शक बताया। समारोह के दौरान अंजली प्रजापति को मिस फेयरवेल तथा अंश विश्वकर्मा को मिस्टर फेयरवेल चुना गया। दोनों विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व, अनुशासन और विद्यालय के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया गया।विद्यालय के निदेशक संजय शुक्ला एवं प्रधानाचार्य नीरज कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने का स्थान नहीं, बल्कि संस्कारों और बेहतर व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है। कक्षा 12 के छात्र-छात्राएं अब जीवन के एक नए पड़ाव पर कदम रख रहे हैं, जहाँ उन्हें अपने ज्ञान और मूल्यों के सहारे सफलता की ओर बढ़ना है।समारोह में विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, गीत एवं कविता पाठ जैसी आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।

पांडेश्वरनाथ धाम पहुंचे सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रयागराज। सोमवार दोपहर में पाण्डेश्वर नाथ महादेव पंडिला मंदिर में सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पाण्डेय ने दर्शन पूजन किया और मंदिर परिसर में बने धर्म शाला में पहुंचे और कहा सवर्ण समाज के लिए हम सदैव आप सभी के साथ हैं उनके जानने वाले एवं सवर्ण समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया इस अवसर पर आशीष तिवारी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गरुण सेना, पण्डित मगन भट्ट सेवक , शिवम मिश्रा, शिव कुमार सिंह, भजन शर्मा, शिवाजी , शुभम मिश्रा आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे।

तीनबत्ती नाका पर अवैध कब्जे के खिलाफ रिक्शा चालकों का बेमुदत आंदोलन

मनपा मुख्यालय के बाहर धरना

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। तीनबत्ती नाका स्थित ऑटो रिक्शा स्टैंड पर कथित अवैध कब्जे और प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में रिक्शा चालक-मालक यूनियन ने सोमवार से बेमुदत आंदोलन शुरू कर दिया है। यूनियन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में रिक्शा चालक भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका मुख्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जिससे शहर में आंदोलन को लेकर हलचल तेज हो गई है।यूनियन के अध्यक्ष कॉ. सुनील चव्हाण ने आरोप लगाया कि तीनबत्ती नाका का रिक्शा स्टैंड प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ), ठाणे से मान्यता प्राप्त है, लेकिन जैतुनपुरा क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहां अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी के पास आरपीआई पार्टी का पत्रानुमा केबिन कार्यालय, चार पक्की लोहे की टपरियां और पांच हाथगाड़ियां लगाकर

जबरन व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा रिक्शा स्टैंड की जगह पर बुलेट बाइक और चारपहिया वाहन खड़े किए जाने से रिक्शा चालकों को यात्रियों को लेने-छोड़ने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन का कहना है कि इस समस्या को लेकर भिवंडी महानगरपालिका, शहर यातायात विभाग और पुलिस प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दी गईं। शहर यातायात विभाग ने भी 25 नवंबर 2025 को महानगरपालिका को पत्र भेजकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन की कथित लापरवाही से नाराज रिक्शा चालकों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। सोमवार सुबह यूनियन पदाधिकारियों और चालकों ने मनपा मुख्यालय के सामने बेमुदत धरना शुरू किया। कॉ. सुनील चव्हाण ने चेतावनी दी कि जब तक रिक्शा स्टैंड से अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।उन्होंने आगे कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो मंगलवार से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा और 11 फरवरी को ऑटो रिक्शाओं के साथ महानगरपालिका का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

भिवंडी में दो गुटों में मारपीट और पथराव, कई आरोपी नामजद

पुलिस ने दर्ज किए अलग-अलग मामले

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर के भाग्यनगर -कामतघर इलाके में आपसी विवाद के चलते दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है। इस मामले में भिवंडी शहर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध दर्ज किए हैं। पुलिस ने नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहली शिकायत सिद्धांत अशोक पाईकराव ने कामतघर ने दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि 7 फरवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे चौधरी चौक, भाग्यनगर इलाके में चेतन सरदार, लवकेश वरगट, ऋषिकेश बरगट, माने, प्रतिक चायनीज वाला,बबल्या बोडवे,दादु, और उनके साथ मौजूद 20 से 25 अज्ञात लोगों ने मिलकर उन पर हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने लकड़ी और पत्थरों से मारपीट की, जिससे शिकायतकर्ता घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं, दूसरी ओर भाजी विक्रेता अभिषेक राम अवतार वर्मा (20) ने भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी दिन यशवंत चौधरी चौक इलाके में सिद्धांत अशोक पाईकराव ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस शिकायत पर भी अलग से मामला दर्ज किया है। सुत्रो के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जो अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। भिवंडी शहर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सभी आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच संबंधित पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और ठगी, आरोपी गिरफ्तार

भिवंडी।शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म और लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। निजामपुरा पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी तौफिक मोहम्मद हारून अंसारी (28), निवासी म्हाडा कॉलोनी, नदी नाका, भिवंडी ने शादी का झूठा वादा कर महिला के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। घटना जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2026 के बीच म्हाडा कॉलोनी, नदी नाका और भिवंडी-कल्याण रोड स्थित साई इंटरनेशनल लॉजिंग एंड बोर्डिंग में हुई।आरोप है कि आरोपी ने महिला से विभिन्न बहानों से कुल 1 लाख 40 हजार रुपये भी लिए और वापस नहीं किए। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसका विश्वास जीता और बाद में मुकर गया। निजामपुरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 351(2), 352, 64(2) (ड) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 8 फरवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक शिवाजी पाटिल कर रहे है।

भिवंडी में हनीट्रैप कर ब्लैकमेलिंग, लाखों की ठगी, तीन आरोपियों पर केस दर्ज

भिवंडी। शहर में हनीट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग कर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शांतिनगर पुलिस ने एक कारोबारी की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है,फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता जमीर नविद पटेल (36), निवासी महापोली, भिवंडी ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी इशरत टोपीवाला, शहनाज इब्राहिम टोपीवाला और इरशाद इब्राहिम टोपीवाला (सभी निवासी गुजरात) ने आपसी संगनमत कर उन्हें हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया।शिकायत के मुताबिक, घटना 26 अप्रैल 2024 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच भिवंडी के वंजारपट्टी नाका स्थित एक लॉज में हुई। आरोप है कि आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता को लॉज में बुलाकर उनका वीडियो बना लिया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर बार-बार पैसे और कीमती सामान की मांग की। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उनसे आईफोन 14 प्रो मैक्स, दो मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, एप्पल वॉच, सोने की अंगूठी, कंगन, कानों के झुमके, दो एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत कई महंगी वस्तुएं और नकदी ठगी कर ली। शांतिनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 308(2),352 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक रविद्र आव्हाड कर रहे है।

भिवंडी में सेंधमारी की तीन वारदातें, लाखों के मोबाइल व आभूषण चोरी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले दो दिनों में अज्ञात चोरों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपये के मोबाइल फोन, आभूषण और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। तीनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पहली घटना भोईवाडा पुलिस स्टेशन की सीमा में रोशनबाग परिसर स्थित आजीम कॉम्प्लेक्स में सामने आई।यहां के निवासी साजिद अली गुलाम रसूल खान ने शिकायत दर्ज कराई है कि अज्ञात चोरों ने उनके घर क्रमांक 1060 का ताला तोड़कर प्रवेश किया और करीब 12,900 रुपये कीमत के 12 पीतल के नल, 5 स्टील नल और नकदी चोरी कर ली। दूसरी घटना शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गुलजार नगर कचेरीपाडा स्थित यूनुस अपार्टमेंट में हुई। यहां के रहने वाली शाहजहान सलीम शेख ने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोलकर अलमारी से करीब 2 लाख 45 हजार रुपये कीमत के सोने के आभूषण और एक कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

तीसरी और सबसे बड़ी वारदात कल्याण नाका, गोपाल नगर स्थित 'सिटी जोन' नामक मोबाइल दुकान में हुई। दुकान मालिक प्रकाश झुमक लाल जैन के अनुसार 6 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने दुकान की छत के सीमेंट शीट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और 22 लाख 61 हजार 992 रुपये कीमत के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर फरार हो गए। भोईवाडा व शांतिनगर पुलिस ने उक्त मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। लगातार हो रही सेंधमारी की घटनाओं से नागरिकों में चिंता बढ़ गई है।

भिवंडी मनपा में महापौर को लेकर सियासत तेज

सेकुलर फ्रंट का दावा, सपा को उपमहापौर पद का ऑफर -सांसद सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी महानगरपालिका में महापौर पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सेकुलर फ्रंट ने महापौर पद पर अपना दावा ठोकते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) को उपमहापौर पद देने का प्रस्ताव रखा है। सांसद सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे ने स्पष्ट कहा है कि मनपा में सेकुलर फ्रंट का ही महापौर होना चाहिए और इसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

सांसद सुरेश म्हात्रे ने बताया कि जब सेकुलर फ्रंट की स्थापना हुई थी, तब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गट) और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ आए थे। फिलहाल कांग्रेस के 30 और राकांपा के 12 नगरसेवक मिलाकर कुल 42 सदस्य सेकुलर फ्रंट के साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के 6 नगरसेवकों ने दूरी बना ली है, जिससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी छह विजयी नगरसेवकों और उनके क्षेत्रों के नागरिकों से अपील

करते हुए कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को सेकुलर फ्रंट के साथ आने के लिए समझाए। उन्होंने कहा कि सेकुलर विचारधारा को मजबूत करने के लिए सभी सहयोगी दलों का साथ आना जरूरी है। सांसद म्हात्रे ने यह भी कहा कि सेकुलर फ्रंट समाजवादी पार्टी को सम्मान देते हुए उपमहापौर पद देने के लिए तैयार है, ताकि गठबंधन मजबूत रहे और स्थिर नेतृत्व मिल सके। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि अगले दो दिनों में समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं हुआ, तो सेकुलर फ्रंट छोटे दलों और अन्य पक्षों के साथ मिलकर अपना महापौर बनाने का निर्णय ले सकता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को 30 सीटों के साथ जनता ने सबसे बड़ा जनादेश दिया है और राकांपा के 12 नगरसेवकों का समर्थन भी उनके साथ है। ऐसे में सेकुलर फ्रंट के पास मजबूत संख्या बल है और महापौर पद पर उनका अधिकार बनता है। भिवंडी मनपा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण छोटे दलों और गठबंधनों की भूमिका अहम हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में महापौर चुनाव को लेकर नए समीकरण बन सकते हैं और गठबंधन की राजनीति निर्णायक साबित होगी।

सोने की चेन और ऑनलाइन खाते से ठगी, आरोपी फरार

भिवंडी। शहर में धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने पहचान का फायदा उठाकर महिला से सोने की चेन और ऑनलाइन खाते से पैसे हड़प लिए। शांतिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 34 वर्षीय रंजना आलिंद्र सिंह, जो भादवड पाइप लाइन क्षेत्र में रहती हैं, ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी चंद्रकांत काटेस्कर (30), निवासी कोलीवली कावाड, भिवंडी ने विश्वास में लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक दोनों एक कंपनी में साथ काम करते थे और आपसी पहचान होने के कारण पीड़िता आरोपी पर भरोसा करती थीं। आरोप है कि 17 फरवरी 2024 को आरोपी महिला के साथ कुर्ला जाने के बहाने गया और रास्ते में विश्वास में लेकर करीब 97 हजार रुपये कीमत की 10 ग्राम वजन की सोने की चेन अपने पास ले ली। इसके बाद आरोपी ने महिला के नाम से ऑनलाइन अकाउंट बनाकर उसमें से करीब 40 हजार रुपये भी निकाल लिए और फरार हो गया। पीड़िता ने जब आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की तो वह टालमटोल करता रहा, जिसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शांतिनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया है। जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक के.जी.पोटे कर रहे है।

जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में भाजपा नंबर एक पार्टी

महायुति की विकास राजनीति पर ग्रामीण जनता की मुहर– भाजपा मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन का प्रतिपादन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार की विकासोन्मुख राजनीति पर मतदाताओं ने विश्वास की मुहर लगाई है। इसी का परिणाम है कि 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समिति चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी नंबर एक पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा महायुति को भारी सफलता मिली है, जबकि कई स्थानों पर कांग्रेस का सफाया हो गया है और उबाठा गुट का पूरी तरह पराभव हुआ है। यह प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख श्री. नवनाथ बन ने सोमवार को किया।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे।

श्री. बन ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना तथा स्व. अजितदादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है। महायुति सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों का चेहरा-मोहरा बदला है और ग्रामीण विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।

सावरकर का नाम लेने का राऊत को कोई अधिकार नहीं

श्री. बन ने कहा कि राहुल गांधी ने लगातार स्वातंत्र्यवीर सावरकर का अपमान किया है, लेकिन इस पर विरोध जताने का साहस जिनमें नहीं है, ऐसे संजय राऊत को सावरकर जी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

स्वातंत्र्यवीर सावरकर का सम्मान केंद्र की भाजपा-एनडीए सरकार ने सदैव किया है। सावरकर पर अपशब्द बोलने वालों को वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे ने जूतों से मारा होता, ऐसा भी उन्होंने कहा।

राऊत को संघ नहीं दिखता, लेकिन पाकिस्तान दिखता है

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का कार्य कर रहा है तथा चरित्रवान पीढ़ियों का निर्माण करता है। संजय राऊत में संघ को समझने की बौद्धिक क्षमता नहीं है, इसलिए वे संघ पर निराधार आरोप लगाते रहते हैं।

पाटकर फाइल्स से राऊत का चरित्र उजागर हुआ है। राऊत को संघ नहीं दिखता, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर दिखता है – ऐसा तीखा तंज श्री. बन ने कसा। उन्होंने यह भी कहा कि बाळासाहेब ठाकरे जीवित रहते हुए राऊत को संघ और स्वयंसेवकों के प्रति उनकी भावना समझनी चाहिए थी।

क्या उद्धव ठाकरे विधायक पद बचाने के लिए उबाठा सेना राहुल गांधी के चरणों में अर्पित करेंगे?

श्री. बन ने सवाल उठाया कि विधायक पद की अवधि समाप्त होने के बाद उद्धव ठाकरे को पुनः विधान परिषद में जाने के लिए कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। आने वाले एक-दो महीनों में, क्या उद्धव ठाकरे अपनी विधायक पद की कुर्सी बचाने के लिए अपनी पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चरणों में अर्पित करेंगे?

देश अमेरिका का गुलाम नहीं, संजय राऊत कांग्रेस के गुलाम बन चुके हैं

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता हो चुका है, जिसमें आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। कृषि को टैरिफ से बाहर रखा गया है और कृषि से जुड़ी आवश्यक वस्तुएँ अमेरिका से आयात नहीं की जाएँगी, यह सरकार ने स्पष्ट किया है।

कांग्रेस की गुलामी स्वीकार करने के कारण संजय राऊत बेतुकी टीका-टिप्पणी और आरोप करने को मजबूर हो गए हैं, ऐसा भी श्री. बन ने कहा।

गुजरात-स्टारलिंक एलओआईः सुदूर क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने लन मस्क की स्पेस एक्स की सब्सिडियरी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपसी सहयोग के आशय पत्र (एलओआई) का विनिमय किया है। इस समझौते के बाद राज्य के ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों को डिजिटली कनेक्ट किया जा सकेगा। इससे सुदूरवर्ती, दूरदराजी तथा कम टेलीकॉम सुविधा और नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में हाईस्पीड सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

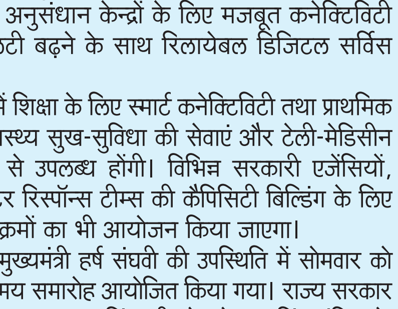

इस एलओआई अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), ई-गवर्नेंस सुविधाओं, सरकारी विद्यालयों, जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष, पोर्ट्स, वन्यजीव अभयारण्यों के क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है। यह एलओआई नर्मदा तथा दाहोद जैसे जिलों सभी जिलों में डिजिटल इन्क्लूजन के लिए महत्वपूर्ण कदम बनेगा। इससे पुलिस आउटपोस्ट्स, आपदा प्रबंधन केन्द्रों, वन्यजीव मॉनिटरिंग तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों के लिए मजबूत कनेक्टिविटी द्वारा सिक्योरिटी तथा स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ रिलायेबल डिजिटल सर्विस डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी।

इसके साथ ही राज्य के स्कूलों में शिक्षा के लिए स्मार्ट कनेक्टिविटी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में स्वास्थ्य सुख-सुविधा की सेवाएं और टेली-मेडिसीन सुविधाएं आसानी से एवं तेजी से उपलब्ध होंगी। विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विभागों, विद्यालयों और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स की कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए भविष्य में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में सोमवार को गांधीनगर में यह एलओआई विनिमय समारोह आयोजित किया गया। राज्य सरकार की ओर से उद्योग आयुक्त पी. स्वरूप तथा स्टारलिंक की ओर से स्टारलिंक इंडिया के हेड प्रभाकर जयकुमार ने इस एलओआई का परस्पर आदान-प्रदान किया।

टोरंटो में शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में भारतीय-कनाडाई की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच

टोरंटो में एक भारतीय-कनाडाई की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। 37 साल के व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गोली मार दी। कनाडा के टोरंटो से एक भारतीय-कनाडाई व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। 37 साल के व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गोली मार दी। मृत व्यक्ति की पहचान चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में की। वह कनाडा के ब्राम्पटन में रहता था।

पुलिस ने बताया कि कि शनिवार को, लगभग 3:31 बजे, पुलिस ने रेक्सडेल बुलेवार्ड और हाईवे 27 पर स्थित वुडबाइन शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गोलीबारी की जानकारी मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पीड़ित को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि गोली मारने वाले संदिग्ध, एक गाड़ी में बैठकर घटनास्थल से भाग गए। पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नंदकुमार मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे और कनाडा में एक आईटी प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे थे। इस साल टोरंटो में गोलीबारी से यह तीसरी हत्या है।

कनाडा के सीटीवी न्यूज़ के अनुसार, घटनास्थल से ली गई तस्वीरों में एक सफेद एसयूवी दिखाई दे रही है, जिसकी विंडशील्ड पर गोलियों के निशान हैं और ड्राइवर की तरफ की खिड़की टूटी हुई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार राजिम कुंभ कल्प में व्यवस्था को लेकर तहसीलदार देवांगन एवं पूर्व मेला अध्यक्ष प्रताप परख से चर्चा राजिम में- राजीव अवस्थी

रायपुर श्री पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार दिनांक 12 13 14 फरवरी 2026 को राजीव कुंभ कल्प में होने जा रहा है श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी का दिव्य दरबार राजीव कुंभ कल्प में विगत कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। पण्डोखर सरकार जी के दिव्य दरबार के व्यवस्था को लेकर आज पंडोखर सरकार शिष्य मंडल के सदस्य राजीव अवस्थी,राकेश अग्रवाल ,जितेंद्र सोनी, एवं अन्य शिष्यों ने आज राजिम कुंभ कल्प में गरियाबंद तहसीलदार देवांगन एवं प्रताप परख से चर्चा हुआ साथ ही साथ संत समागम में होने वाले अन्य साधु संतों की व्यवस्था को लेकर भी तहसीलदार साहब एवं प्रताप परख जी के साथ संत समागम में भ्रमण किये

और वहां पर उपस्थित संत दंडी स्वामी जी से पंडोखर सरकार शिष्य मंडल ने आशीर्वाद लिया और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

वेलोसिटी का एआई शिपिंग पर बड़ा दांव, 100 करोड़ के निवेश से ई-कॉमर्स में लाएगी क्रांति

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ई-कॉमर्स मंच वेलोसिटी की योजना अगले दो वर्ष में अपने लॉजिस्टिक्स कारोबार 'वेलोसिटी शिपिंग' के विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करने की है। यह निवेश पूरी तरह कंपनी के आंतरिक नकद भंडार और उसके मुख्य कारोबार से होने वाली आय से किया जाएगा।

कंपनी बयान के अनुसार, 2025 में शुरुआत के बाद से वेलोसिटी शिपिंग (पुराना नाम शिपफास्ट) ने 900 से अधिक ब्रांड जोड़े हैं। मंच पर ऑर्डर की मात्रा में फिलहाल मासिक आधार पर 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है और अब वेलोसिटी की कुल आय में इसका करीब 40 प्रतिशत का योगदान है। इसमें कहा गया कि 100 करोड़ रुपये का यह निवेश रणनीतिक नियुक्तियों, उत्पाद विकास और लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित नवाचार पर केंद्रित होगा।

कंपनी ने कहा कि वह अपनी 'शिपिंग' दल को दोगुना करने की योजना बना रही है और अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियां भी कर चुकी है। वेलोसिटी शिपिंग डेल्हीवरी, एकार्ट, अमेजन, ब्लू डार्ट, ब्लिट्ज, पिकंडेल और एक्सप्रेसबीज सहित कई तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स भागीदारों के साथ काम करती है।

देशभर में 19, 000 से अधिक 'पिनकोड' में सेवाएं देती है। वेलोसिटी के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिरूप मेढेकर (सीईओ) ने कहा, '' हमने वेलोसिटी की शुरुआत डिजिटल-प्रथम ब्रांड की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक, 'पूंजी तक पहुंच' को हल करने के उद्देश्य से की थी। हजारों संस्थापकों के साथ काम करते हुए यह स्पष्ट हुआ कि लॉजिस्टिक्स और पूर्ति भी विकास के लिए उतनी ही अहम बाधाएं हैं, लेकिन मौजूदा समाधानों को डिजिटल-प्रथम ब्रांडों के बेहतर समर्थन के लिए विकसित करने की जरूरत है।''

उन्होंने कहा, '' 100 करोड़ रुपये की यह प्रतिबद्धता भारत के ई-कॉमर्स परिवेश के लिए श्रेणी-निर्धारक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करते हुए शिपिंग पर दोगुना जोर देने के हमारे दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाती है।'' वर्ष 2020 में स्थापित वेलोसिटी... पूंजी, लॉजिस्टिक्स, इनसाइट्स और एआई-आधारित समाधानों से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है।

एशियाई चैंपियनशिप : रोमांचक शूट ऑफ में स्वर्ण पदक से चूकी मनु भाकर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ओलंपिक की दोहरी कांस्य पदक विजेता मनु भाकर सोमवार को यहां स्वर्ण पदक जीतने के बेहद करीब पहुंचकर रोमांचक शूट ऑफ में पिछड़ गईं जिससे उन्हें एशियाई चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा जबकि उनकी साथी भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह को कांस्य पदक मिला। महाद्वीपीय प्रतियोगिता के मौजूदा सत्र के सबसे करीब मुकाबले में से एक में स्वर्ण पदक विजेता एनगुयेन थुय ट्रंग और मनु दोनों ने फाइनल में समान 35 का स्कोर किया। इसके बाद मुकाबला शूट ऑफ में खिंचा जिसमें वियतनाम की खिलाड़ी ने बाजी मार ली।

फाइनल में पूर्व एशियाई एयर पिस्टल चैंपियन ट्रंग, मनु, ईशा और ओलंपियन रिदम सांगवान सभी स्वर्ण के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ईशा ने पहली सीरीज में परफेक्ट पांच अंक से शुरुआत की जबकि मनु और ट्रंग ने चार-चार अंक के निशाने लगाए। हर सीरीज के बाद पदक की दौड़ में स्थिति बदल रही थी लेकिन छठी सीरीज में परफेक्ट पांच के साथ वियतनाम की खिलाड़ी ने दो अंक की बढ़त बना ली। मनु और ईशा ने ट्रंग की खराब सातवीं सीरीज का फायदा उठाया जिसमें वह सिर्फ एक निशाना लगा पाईं जिससे अंतर कम हो गया।

आठवीं सीरीज के आखिर में 30 के स्कोर के साथ आगे चल रही ईशा नौवीं सीरीज में अपने सभी शॉट चूक गईं और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अंतिम सीरीज में मनु ने तीन निशाने लगाए जबकि ट्रंग दो की निशाने लगा पाईं जिससे दोनों का कुल स्कोर 35 हो गया और मुकाबला शूट ऑफ में खिंचा इससे पहले ईशा ने 'प्रिसिन' और 'ड्यूलिंग' चरण के क्वालीफिकेशन दौर में 589 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके बाद मनु (584) रहीं। रिदम ने भी फाइनल में जगह बनाई जिससे आठ में से तीन निशानेबाज भारतीय थे।

ईशा, मनु और रिदम की तिकड़ी ने कुल 1, 751 अंक के साथ टीम स्वर्ण जीता। चीनी ताइपे को 1, 735 अंक के साथ रजत जबकि वियतनाम को 1, 729 अंक के साथ कांस्य पदक मिला। जूनियर 25 मीटर पिस्टल फाइनल में नाम्या कपूर ने रोमांचक शूट ऑफ में स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया की रिहादतुल अस्यिफा को पछाड़ा। अंजलि भागवत ने कांस्य पदक जीता। जूनियर भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में टीम स्वर्ण भी जीता।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची

सिडनी **(एजेंसी)**। भारतीय महिला क्रिकेट टीम मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है जो 15 फरवरी से शुरू होगी। भारत के इस दौरे में तीन टी20 मैच, तीन वनडे इंटरनेशनल और एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच शामिल होगा। हरमनप्रीत कौर सभी फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंधाना उप-कप्तान बनी रहेंगी। सोमवार को बीसीसीआई विमेन द्वारा जारी एक वीडियो में भारतीय क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए काफी उत्साहित दिख रही थीं। टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज स्मृति ने आरसीबी का दूसरा डब्ल्यूपीएल खिताब जीतने के बाद हुए जश्न और नेशनल ड्यूटी पर वापस आने के बारे में बात की।

बीसीसीआई द्वारा एक्स पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'बहुत व्यस्त था, मैं कहूंगी, लेकिन इसके लायक था। हमने बहुत मजे किए, लेकिन अब नेशनल ड्यूटी पर वापस आ गए हैं।' भारत अपना पहला टी20आई मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 15 फरवरी को खेलेगा, इसके बाद दूसरा टी20आई मैच कैनबरा के मनुका ओवल में 19 फरवरी को और तीसरा मैच एडिलेड ओवल में 21 फरवरी को होगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई सीरीज जून में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए महत्वपूर्ण तैयारी होगी। टी20आई के बाद ध्यान वनडे सीरीज पर जाएगा, जो 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में शुरू होगी। इसके बाद टीमें दूसरे और तीसरे वनडे के लिए होबार्ट के बेलेरिव ओवल जाएंगी, जो क्रमशः 27 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाएंगे। यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें वनडे में मिलेंगी, जब पिछले साल अक्टूबर में महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट से जीत हासिल की थी। यह ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी एलिसा हीली की आखिरी सीरीज भी होगी क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि वह भारत दौरे के बाद सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी। यह दौरा प्रतिष्ठित एक टेस्ट मैच के साथ समाप्त होगा, जो 6 से 9 मार्च तक पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।

इंग्लिश प्रीमियर लीग : हैलेंड के गोल से मैनचेस्टर सिटी ने लीवरपूल को हराया

लंदन **(एजेंसी)**। एर्लिंग हैलेंड के अंतिम लम्हों में पेनल्टी पर दागे गोल की बदौलत मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में लीवरपूल को 2-1 से हराकर खिताब की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। नॉर्वे के हैलेंड ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में गोल दागकर रविवार को अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। मैनचेस्टर सिटी की टीम 25 मैच में 50 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। अब उसके और शीर्ष पर चल रहे आर्सेनल के बीच छह अंक का अंतर है। लीवरपूल को 74वें मिनट में डोमीनिक जोबोज्लाई ने बढ़त दिलाई थी जिसके 10 मिनट बाद बर्नार्डो सिल्वा ने स्कोर 1-1 कर दिया। हैलेंड ने इसके बाद पेनल्टी पर गोल दागकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। एक अन्य मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने ब्राइटन को 1-0 से हराकर 12 मैच से चले आ रहे जीत के इंतजार को खत्म किया।

यूको बैंक की एफडी स्कीम

1 लाख रुपये जमा करें और मैच्योरिटी पर पाएं 38, 000 रुपये तक का पक्का ब्याज!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की और रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखा। पिछले साल की तुलना में इसमें 1.25 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जिससे अब लोन सस्ते हो गए हैं। हालांकि, एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दरें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन कुछ बैंक अभी भी आकर्षक ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। इसी कड़ी में, यूको बैंक की नई एफडी स्कीम ने निवेशकों का ध्यान खींचा है।

यूको बैंक अपने ग्राहकों को 2.90 प्रतिशत से लेकर 7.95 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर एफडी विकल्प दे रहा है। खासतौर पर, बैंक की 444 दिनों की विशेष एफडी स्कीम में सामान्य ग्राहकों को 6.45इ, वरिष्ठ नागरिकों को 6.95इ, स्टाफ को 7.45इ और रिटायर्ड वरिष्ठ स्टाफ को 7.95इ का ब्याज मिलता है। वहीं, 5 साल की एफडी में सामान्य ग्राहकों को 6.00इ और वरिष्ठ नागरिकों को 6.50इ ब्याज दर मिल रही है।

अगर आप सामान्य ग्राहक हैं और 5 साल के लिए 1 लाख रुपये यूको बैंक में जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको कुल 1, 34, 686 रुपये मिलेंगे, जिसमें 34, 686 रुपये का निश्चित ब्याज शामिल है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही राशि 1, 38, 042 रुपये, जिसमें 38, 042 रुपये का ब्याज शामिल है। एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको निवेश की पूरी राशि के साथ-साथ ब्याज का निश्चित पैसा भी समय पर मिल जाता है, यानी कोई अनिश्चितता या छुपा नियम नहीं। यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो सुरक्षित निवेश के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं।

यूको बैंक की यह एफडी स्कीम उन लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बन रही है जो अपनी बचत को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और तय ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर बड़ा रिटर्न पाना चाहते हैं।

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' को अदालत से बड़ी राहत, फिल्म की रिलीज का रास्ता हुआ साफ

मुंबई। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' ने एक बड़ी कानूनी लड़ाई जीत ली है। मुंबई की एक अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। यह केस दिवंगत गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी, सनोबर शेख ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि यह फिल्म उनके पिता की जिंदगी पर आधारित है और इसके लिए उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई।

सनोबर शेख ने फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और लेखक हुसैन जैदी के खिलाफ सिविल केस किया था। सनोबर का आरोप था कि फिल्म में उनके पिता को एक गैंगस्टर के रूप में दिखाया गया है और बिना परिवार की इजाजत के कहानी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मांग की थी कि फिल्म की रिलीज रोक दी जाए।

सिविल कोर्ट के जज एच सी शेंडे ने सनोबर की याचिका को खारिज करते हुए कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कोर्ट को पता चला कि सनोबर ने मुकदमा करने से पहले मेकर्स को नोटिस भेजकर 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जब शिकायत सिर्फ पैसे से जुड़ी हो तो फिल्म की रिलीज रोकना कानूनन सही नहीं है।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सनोबर को फिल्म के बारे में काफी समय से पता था, लेकिन वह कोर्ट तब पहुंचीं जब फिल्म रिलीज होने वाली थी। जज ने फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग भी ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि यह 'न्यायिक सेंसरशिप' जैसा होगा, जिसकी इजाजत कानून नहीं देता।

मेकर्स के वकीलों का कहना है कि यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और इसमें जरूरी डिस्क्लेमर भी दिए गए हैं। 'ओ रोमियो' एक एक्शन से भरपूर गैंगस्टर ड्रामा है, जिसमें शाहिद कपूर एक गनमैन की भूमिका निभा रहे हैं। 'हैदर' और 'कमीने' के बाद विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर की यह तीसरी बड़ी फिल्म है।यह फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, सनोबर शेख के वकीलों का कहना है कि वे अब इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

खुद को खोना मंजूर नहीं, वीर पहाड़िया से ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने मानसिक शांति पर की बातचीत

आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज के इंतजार के बीच अभिनेत्री तारा सुतारिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मीडिया गलियारों में चर्चा है कि तारा और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि, दोनों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन लंबे समय से दोनों को साथ न देखे जाने के बाद इन अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच, तारा ने एक इंटरव्यू में अपनी मानसिक शांति और आसपास की नेगेटिव एनर्जी से निपटने पर खुलकर बात की है।

एले इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में तारा ने अपनी निजी जिंदगी और करियर के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब 'अपनी शांति की रक्षा करना' सीख लिया है। तारा ने साफ किया कि उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ फिल्में नहीं हैं।

तारा ने कहा, 'मैंने हमेशा माना है कि सफलता अंदर से आती है। मन की शांति और खुद को जानना ही मेरा लक्ष्य रहा है। मैं खुद को खोने के बजाय एक फिल्म खोना पसंद करूंगी।'

तारा ने आगे कहा कि एक एक्टर होने के नाते लोग आपके बारे में कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें कभी हर किसी को सच्चाई बताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उनके मुताबिक, जब तक उन्हें और उनके करीबियों को सच पता है, तब तक बाकी बातें मायने नहीं रखतीं।तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने साल 2025 की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी और अक्सर उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ देखा जाता था। उनके बीच की बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आती थी, लेकिन अब गलियारों में यह चर्चा तेज है कि तारा और वीर का ब्रेकअप हो गया है। हाल ही में वीर के जन्मदिन (1 फरवरी) और अन्य कई मौकों पर तारा की गैरमौजूदगी ने इन अफवाहों को हवा दी।

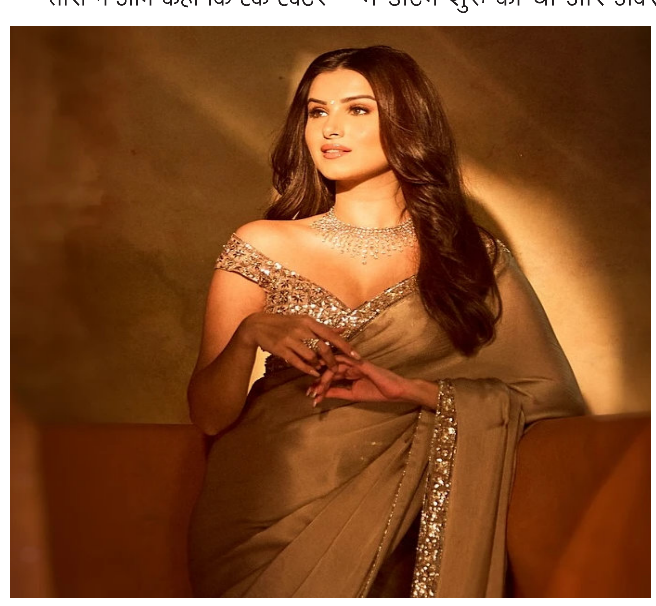

सोने-चांदी की चमक लौटी : गिरावट के बाद निवेशकों की चांदी, ईटीएफ में आया उछाल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी उथल-पुथल के बाद अब कीमती धातुओं के दिन फिरते नजर आ रहे हैं। सोमवार की सुबह निवेशकों के लिए खुशियां लेकर आई, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार रिकवरी दर्ज की गई है। पिछले कुछ सत्रों में जो मुनाफा बाजार की अस्थिरता की भेंट चढ़ गया था, उसकी भरपाई अब तेजी से हो रही है। इस सुधार का सबसे बड़ा असर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) पर देखने को मिला, जहां निवेशकों ने जमकर खरीदारी की।

महीने की शुरुआत में आई गिरावट को पीछे छोड़ते हुए वायदा बाजार में शानदार बढ़त देखी गई। अप्रैल में मैच्योर होने वाला सोना करीब 2इ की मजबूती के साथ 1, 58, 500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू गया। इसी तरह जून के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी उत्साह बना रहा। लेकिन असली बाजी चांदी ने मारी। मार्च एक्सपायरी वाली चांदी की कीमतों में लगभग 6इ की भारी तेजी आई, जिससे इसके भाव 2, 64, 885 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए। मई के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी 4इ तक का इजाफा देखा गया, जो बाजार में लौटते भरोसे का संकेत है।

कीमती धातुओं में हालिया गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें थीं। दरअसल, सीएमई ग्रुप ने ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की सीमा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बड़े ट्रेडर्स को मजबूरी में अपनी पोजीशन बेचनी पड़ी। इसके साथ ही, अमेरिका में केविन वॉर्श को अगले फेडरल रिजर्व चेयरमैन के तौर पर नामांकित किए जाने की खबर ने भी बाजार को प्रभावित किया।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्रमांक : ACD/1058/ए.ई. (एसडब्ल्यूएम)D/दिनांक : 09/02/2026

ईओआई

सहायक आयुक्त, डी-वार्ड, जोबनपुत्रा कंपाउंड, नाना चौक, मुंबई-400007 द्वारा 'डी-वार्ड में रमजान ईद के दौरान सफाई कार्य हेतु एनजीओ के श्रमिक उपलब्ध कराने' के लिए सीलबंद ईओआई/कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्त कोटेशन प्रपत्र सहायक अभियंता (एसडब्ल्यूएम), डी-वार्ड के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में 10.02.2026 से 16.02.2026 तक सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच प्राप्त किए जा सकते हैं।

मोम-सील किया हुआ ईओआई/कोटेशन सहायक अभियंता (एसडब्ल्यूएम), डी-वार्ड के कार्यालय में अंतिम तिथि 16.02.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक पहुँचना चाहिए। प्राप्त ईओआई/कोटेशन उसी दिन शाम 4.00 बजे खोले जाएंगे। डी-वार्ड में पूर्व में सफाई कार्य का अनुभव रखने वाले एनजीओ को प्राथमिकता दी जाएगी।

ईओआई/कोटेशन दस्तावेज़ डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।

पीआरओ/2920/विज्ञा./2025-26

सहायक अभियंता (एसडब्ल्यूएम), डी-वार्ड

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

पश्चिम रेलवे-वड़ोदरा

विभिन्न पुल कार्य

ई–निविदा सूचना सं. DYCE-BR-BRC-23R-2025-26

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज–लाईन) वडोदरा, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा–390004 द्वारा निम्नानुसार कार्यों हेतु ई–निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। **क्रम सं.1: निविदा सं. DYCE–BR–BRC–23R–2025–26 कार्य का नाम:** "रतलाम मंडलः– रतलाम मंडल के SSE/पुल/रतलाम के क्षेत्राधिकार में पु. सं. 226 UP/DN, 317 UP/DN के विभिन्न प्रमुख स्टील ट्रैक पुलों एवं DGA–RTM–NAD के विभिन्न ROBs के गढ्ढेदार और छिद्रित ब्रासिंग एंगल्स, क्रॉस गर्डर बॉटम एंगल्स, टॉप फ्लेंजीस कवर प्लेट्स, खराब प्लेट्स, OHE प्रॉटेक्शन स्क्रीन, इंसपेक्शन क्रेडल्स, एंटी क्रेश बेरियर, ड्रेनेज स्पाउट्स, खराब रिवेट्स का प्रतिस्थापन और मेटलाइजींग के अन्य परचुरण कार्य। (पुनःआमंत्रित–1)" **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में.) :** 6,18,82,189.38 **जमा कराने हेतु बिड सुरक्षा (₹ में.) :** 4,59,400.00 **ई–निविदा जमा करने एवं ई–निविदा खुलने की तारीख एवं समयः** निविदा दिनांक 12/03/2026 को 15:00 बजे से पहले ऑनलाईन जमा करानी होगी एवं उसी तिथि को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी। **वेबसाईट विवरण एवं नोटीस हेतु स्थान जहाँ से संपूर्ण विवरण देखे जा सकते हैं आदिः वेबसाईटः** @www,ireps.gov.in उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज लाईन), वडोदरा, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा–4, BRC-352

हमें फॉलो करें: DRMBRCWR • drm_vadodara

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

मोटराइज़्ड बोगी फ्रैम की मरम्मत/पुनर्वसन

निविदा सूचना सं. EL/TRS/BRC/2025-26/5

दिनांक : 04/02/2026

निविदा सं. ELSBRC2526MBOGIE4

(I) कार्य का नाम उसके स्थान सहितः कार्य के अवकाश अनुसार 3 फैज लोकोमोटीव के मोटराइज़्ड बोगी फ्रैम की मरम्मत/पुनर्वसन (विद्युत लोको शेड, वडोदरा, प.रे.) **(ii) कार्य की अनुमानित लागतः** ₹ 3,07,27,200/– **(iii) जमा करने की बीड सुरक्षाः** ₹ 3,03,600/– **(iv) निविदा जमा कराने एवं निविदा खोलने की तारीख एव समयः** निविदा दिनांक **06/03/2026** को 15:00 बजे तक इलेक्ट्रॉनिकली जमा की जाएगी एव दिनांक **06/03/2026** को 15:30 बजे के बाद खोली जाएगी **(v) वेबसाइट का विवरण, नोटीस बोर्ड का स्थान जहाँ से संपुर्ण विवरण देखे जा सकते हैं एवं कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र खरीदे जा सकते हैं:** https://www.ireps.gov.in विद्युत लोको शेड, नवा यार्ड, वडोदरा वरि. मंडल विद्युत अभियंता (TRS), विद्युत लोको शेड, नवायार्ड, वडोदरा–390002, गुजरात। BRC-350

हमें फॉलो करें: DRMBRCWR • drm_vadodara

मध्य रेल

भुसावल मंडल

विद्युतीकरण कार्य

निविदा सं.: BSL-L-W-T-11-2026. **कार्य का विवरण :** निम्नलिखित के संबंध में विद्युतीकरण का कामः **भाग ए-** कुंभ मेला 2027 के संबंध में देवलाली, ओढ़ा, खेरवाड़ी और कस्बे सुकने में प्रस्तावित कैंप ऑफिस, **भाग बी-** कुंभ मेले 2027 के संबंध में मेडिकल सुविधाओं का विकास, **भाग सी-** नासिक में कुंभ मेला 2027 के संबंध में सुपरवाइजर रेस्ट हाउस (32 बेड क्षमता) का निर्माण, **भाग डी-** प्लान हेड 64 के तहत अम्ब्रेला वर्क 2025-26 के तहत जेडटीसी नासिक में बेसिक सुविधाओं के साथ 50 बेड वाले महिला आरपीएफ बैरक का निर्माण और जलगाँव और चालीसगाँव प्रत्येक में 20 बेड वाले आरपीएफ बैरक का निर्माण, **भाग ई-** नासिक में कुंभ मेला 2027 के संबंध में नासिक के मौजूदा औआरएच का नवीनीकरण। **अनुमानित लागत :** ₹ 4,17,10,740, **ऑनलाईन बिड सबमिशन का अंतिम दिनांक और समय :** 02.03.2026 को 15.00 बजे, **वेबसाईट विवरण: https://www.ireps.gov.in**

डीईई जीईएन, भुसावल

रेलमदद हेल्पलाईन 139 EXP

एनएसजी हब पर जलाई गई ग्रुप कमांडर की कार, साजिश की आशंका, डीजी को लिखे पत्र में सेना के अफसरों की टीस

चेन्नई । नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के चेन्नई स्थित स्पेशल कंपोजिट ग्रुप, रीजनल हब में 'ग्रुप कमांडर' की कार को आग लगाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विदित रहे कि एनएसजी के रीजनल हब में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। वे कौन लोग हैं, जिन्होंने ग्रुप कमांडर के आवास में घुसकर कार में आग लगा दी, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि कार के निकट एक बोतल मिली थी, जिसमें कुछ देर पहले तक पेट्रोल भरा हुआ था। इस मामले में एनएसजी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आर्मी अफसरों ने डीजी बी. श्रीनिवासन 'आईपीएस' को पत्र लिखा है। इससे कहा गया है कि उक्त घटना से एनएसजी जैसे विशेष बल में माहौल खराब हो रहा है। डीजी एनएसजी से मांग की गई है कि इस मामले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाए। दूसरी तरफ एनएसजी के एक जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि इस केस की जांच चल रही है। एनएसजी की तरफ से कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। घटना को जानबूझकर तूल देने का प्रयास किया जा रहा है।

बता दें कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक, ग्रुप कमांडर के आवास संख्या 27, स्पेशल कंपोजिट ग्रुप, एसयूएनएल रीजनल हब, चेन्नई पर कार जलने की शिकायत मिली थी। अजय खरवार ने 8 नवंबर 2025 को दो बजे आग लगने की सूचना दी थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 324 (4), 326 (बी), 351 (4), 329 (4) के तहत केस दर्ज किया है। सबसे पहले इस मामले में ग्रुप 1 के सूबेदार एडजुटेंट को सूचित किया गया। इसके बाद वे ग्रुप कमांडर के आवास पर पहुंचे। रेंजर 1 लालजी यादव, रेजिमेंट पुलिस नॉन कमीशन ऑफिसर को कॉल किया गया। उनसे फायर ब्रिगेड का इंतजाम करने के लिए कहा गया। इसके बाद लालजी यादव और दूसरे कमांडो भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

प्रारंभ में कमांडो ने खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ देर बाद वहां क्यूआरटी और पानी का टैंकर भी आ गया। सूबेदार मेजर और दूसरे कर्मियों ने देखा कि कार संख्या जेएच 10एजेड 1284 जल रही है। जली हुई कार से दस फीट की दूरी पर प्लास्टिक की एक खाली बोतल पड़ी हुई थी। बोतन के ढक्कन में एक छेद था। उसमें से पेट्रोल की गंध आ रही थी। मेजर आदित्य प्रकाश वीपी और रेंजर 2 निकेश ने सर्च अभियान शुरु किया। पता चला कि ग्रुप कमांडर के आवास का पिछला गेट खुला हुआ था। गार्डन एरिया में कागज के टुकड़े पड़े हुए थे।

कागज पर ग्रुप कमांडर को लेकर अभद्र शब्द लिखे हुए थे। इससे यह मालूम पड़ा कि आग लगने की घटना, महज एक हादसा नहीं था। वह सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई एक वारदात थी। कुछ लोग गैर कानूनी रूप से ग्रुप कमांडर के घर में घुसे और उन्होंने कार में आग लगा दी। एक जनवरी 2026 को 27 'एससीजी' (स्पेशल कंपोजिट ग्रुप), चेन्नई रीजनल हब, एनएसजी के अधिकारियों ने डीजी को पत्र लिखा था। इसमें अधिकारियों ने ग्रुप कमांडर के लिए अपना समर्थन और एकजुटता का प्रदर्शन किया है। इस मामले में कोई सटीक कार्रवाई नहीं हो पा रही। उक्त मामले में कई अधिकारी पहले भी मौखिक और लिखित प्रतिवेदन के तौर पर अपनी बात कह चुके हैं। इससे एनएसजी जैसे बल में माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने डीजी एनएसजी से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाए। यह टीम, घटना की तह तक पहुंच सकती है। जांच का नतीजा और उसके अनुरुप कार्रवाई, इसके द्वारा फोर्स में माहौल खराब होने से रोका जा सकता है। एनएसजी जैसे बल में ये सब होना और शीर्ष नेतृत्व का समय रहते मामला न सुलझा पाना, कई सवाल खड़े करता है।

कुछ अधिकारियों के मुताबिक, एनएसजी हब, चेन्नई में एक गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। हमेशा की तरह, चाहे वह आर्म्ड फोर्सेज हो या एनएसजी, सीनियर लेवल पर समझ की कमी के कारण फैसले लेने में पूरी तरह से रुकावट आ गई है। ऐसा लगता है कि डीजी एनएसजी अभी भी उस लेटर पर चुप बैठे हैं, जो उन्हें भेजा गया था। इस हब के अफसर की कार को कथित तौर पर वहीं के लोगों द्वारा जलाए जाने के वीडियो भी हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस मामले में अन्य रैंक 'ओआर' से जुड़े कार्मिकों द्वारा कोर्ट का रुख किया गया है। ये एनएसजी के लिए ठीक नहीं है। अगर जल्द ही इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो ये फोर्स के लिए ठीक नहीं होगा।

तिरुपति लड्डू विवादः साधु परिषद के अध्यक्ष ने लगाया आरोप- 'सीबीआई रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि

चेन्नई। तिरुपति लड्डू को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच आंध्र प्रदेश साधु परिषद के अध्यक्ष श्रीनिवासानंद सरस्वती ने सोमवार को आरोप लगाया कि तिरुपति के लड्डू पर सीबीआई की रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। उन्होंने दावा किया कि 20 करोड़ रुपये के लड्डू में मिलावट की गई थी।

लड्डू खाने के बाद श्रद्धालु बीमार पड़ सकते हैं

उन्होंने आरोप लगाया कि एक खाद्य माफिया पवित्र लड्डू में मिलावट करने में शामिल है। इसके साथ ही कहा कि रसायन युक्त लड्डू खाने के बाद श्रद्धालु बीमार पड़ सकते हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा, 'सीबीआई ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें पुष्टि की गई है कि तिरुपति के लड्डू में मिलावट थी। सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला है कि 20 करोड़ रुपये के लड्डू में मिलावट की गई थी।' लड्डू में मिलावट के मामले में सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि कुकर्म करने वाले भगवान वेंकटेश्वर के दंड से बच नहीं सकते।

इस से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को तिरुपति लड्डू में मिलावट को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की पिछली सरकार के कार्यकाल में तिरुपति लड्डू बनाने के लिए उपयोग किया गया

घी शौचालय को साफ करने में इस्तेमाल होने वाले रसायन से बना था। नायडू ने कहा कि रसायनों से युक्त मिलावटी घी का इस्तेमाल पांच साल तक लड्डू बनाने में किया गया। उन्होंने कहा कि दो प्रकार के रसायन होते हैं, जिनमें से कुछ वनस्पति मूल के होते हैं, जो महंगे होते हैं। उन्होंने बताया कि पशु वसा की कीमत कम होती है।

अब लग्जरी होटलों में ठहरना हुआ मुश्किल एक रात का किराया जानकार चकरायेगा सिर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अगर आप फरवरी के मध्य में दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए! देश की राजधानी में ठहरना अब मिडिल क्लास क्या अमीरों की जेब पर भी भारी पड़ रहा है। दिल्ली के नामी पांच सितारा होटलों के कमरों का किराया आसमान छू रहा है। कुछ होटलों में तो एक रात का बिल किसी लग्जरी कार की कीमत के बराबर पहुंच गया है।

दौरान दिल्ली में ही रहेंगे।

द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के अनुसार 19 और 20 फरवरी की तारीखों के लिए लगभग सभी कमरे बुक हो चुके हैं। विदेशी मेहमानों और मंत्रियों की आमद के कारण प्रीमियम सुइट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। होटल मैनेजर्स का कहना है कि इतने बड़े स्तर का अंतरराष्ट्रीय आयोजन होटल इंडस्ट्री के लिए बोनस जैसा है लेकिन सामान्य

इस बेतहाशा महंगाई के पीछे कोई शादी या त्यौहार नहीं बल्कि 16 से 20 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है। भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए 35, 000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 20 राष्ट्राध्यक्ष और दर्जनों वैश्विक कंपनियों के सीईओ इस

यात्रियों के लिए जगह मिलना मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार जब भी राजधानी में कोई जी-20 जैसा बड़ा ग्लोबल समिट होता है तो मांग और आपूर्ति का संतुलन बदल जाता है। 100 देशों की मौजूदगी और 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के जुड़ाव ने दिल्ली को नो-वैकेंसी ज़ोन में तब्दील कर दिया है।

सेशेल्स बना भारत का रणनीतिक साथी, पूरे हिंद महासागर में भारत का जाल फैलाने में जुटे हैं पीएम मोदी

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अर्मिनी की भारत यात्रा ऐसे समय हुई है जब हिंद महासागर विश्व राजनीति का नया रणक्षेत्र बनता जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में नई दिल्ली ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ रिश्तों को केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें सामरिक, आर्थिक और तकनीकी ताकत में बदलेगी। यही कारण है कि इस यात्रा ने भारत सेशेल्स संबंधों को एक नए चरण में पहुंचा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अर्मिनी की मौजूदगी में दोनों देशों ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। सबसे बड़ी घोषणा रही सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक सहायता योजना। यह सहायता सामाजिक आवास, विद्युत गतिशीलता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसी ठोस परियोजनाओं पर खर्च होगी। साफ है कि भारत केवल वादे नहीं, जमीन पर दिखने वाले काम चाहता है।

प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि विकास साझेदारी ही दोनों देशों के संबंधों की मजबूत नींव है और भारत के सभी प्रयास सेशेल्स की जरूरतों पर आधारित हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने, वित्त तकनीक और डिजिटल समाधान पर साथ काम करने तथा डिजिटल रूपांतरण में भारत के अनुभव को साझा करने पर सहमति बनी। इससे शासन, सेवा वितरण और पारदर्शिता में तेजी आने की उम्मीद है।

सेशेल्स के सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी समझौता हुआ है। भारत का क्षमता निर्माण कार्यक्रम पहले से ही सेशेल्स के मानव संसाधन को मजबूत करता रहा है। अब इसे और गति दी जाएगी ताकि युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर मिलें। स्वास्थ्य क्षेत्र में सस्ती और अच्छी दवाओं की आपूर्ति, चिकित्सीय पर्यटन और स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर जोर रहेगा।

साथ ही ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर तेजी से काम करेंगे। साफ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, जलवायु बदलाव से निपटने के उपाय खोजे जाएंगे और ऐसी अवसंरचना बनाई जाएगी जो आपदाओं को झेल सके। स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और बिजली से चलने वाले वाहनों पर भी जोर रहेगा। साथ ही पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और खेल के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को और करीब लाने की कोशिश होगी, खास तौर पर युवाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके अलावा, समुद्री पड़ोसी होने की वजह से समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था दोनों देशों के सहयोग का स्वाभाविक क्षेत्र है। समुद्री अनुसंधान, प्रशिक्षण और जानकारी साझा करने में भारत सेशेल्स की मदद करेगा। रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा इस रिश्ते की रीढ़ हैं। सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हिंद महासागर में

शांति और स्थिरता मजबूत होगी। इसके अलावा, दोनों देशों ने एक संयुक्त दृष्टि पत्र जारी करने का निर्णय लिया जो आने वाले वर्षों के लिए सहयोग का मार्गदर्शक होगा। राष्ट्रपति अर्मिनी ने सेशेल्स की आजादी के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। साथ ही यह वही वर्ष है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के भी पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं।

हम आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अर्मिनी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने चेन्नई और मुंबई में स्वास्थ्य, बंदरगाह, जहाजरानी, निवेश और समुद्री उद्योग से जुड़े पक्षों से बातचीत भी की थी। यह यात्रा अक्टूबर 2025 में पद संभालने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है, इसलिए इसका प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह का महत्व है।

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि हिंद महासागर की लहरें सदियों से दोनों देशों के लोगों को जोड़ती रही हैं। व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिलीं और विश्वास की परंपरा मजबूत हुई। सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय ने वहां के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है और पीढ़ी दर पीढ़ी मित्रता को मजबूत किया है।

हम आपको बता दें कि सामरिक नजरिये से सेशेल्स का महत्व बहुत बड़ा है। यह उन समुद्री मार्गों के पास स्थित है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ते हैं। भारत की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का बड़ा हिस्सा इन्हीं मार्गों से गुजरता है। सेशेल्स के साथ मजबूत संबंध भारत को समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और बाहरी ताकतों के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने में मदद देते हैं। यह पूर्वी अफ्रीका और द्वीपीय देशों की ओर भारत का प्राकृतिक सेतु भी है। इस तरह सेशेल्स भारत की हिंद महासागर नीति का एक सामरिक स्तंभ बनकर उभर रहा है।

देखा जाये तो सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा समुद्री राजनीति का स्पष्ट संदेश है। हिंद महासागर में जो देश अपनी मौजूदगी मजबूत करेगा, वही आने वाले समय में व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के खेल में बढ़त लेगा। भारत ने समझ लिया है कि खाली बयान नहीं, निवेश, प्रशिक्षण, तकनीक और सुरक्षा सहयोग ही असली असर पैदा करते हैं। सवाल यह नहीं कि सेशेल्स छोटा देश है या बड़ा, सवाल यह है कि वह कहां स्थित है और किसके साथ खड़ा है। जो ताकतें हिंद महासागर में अपना जाल फैलाना चाहती हैं, उनके लिए यह संकेत है कि भारत अपने पड़ोस को अकेला नहीं छोड़ेगा। विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चलने वाली यह नीति भारत को भरोसेमंद साथी बनाती है।

बहरहाल, अब चुनौती यह है कि घोषित योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरें। यदि भारत ने गति और निरंतरता बनाए रखी, तो सेशेल्स जैसे साझेदार केवल मित्र नहीं रहेंगे, बल्कि हिंद महासागर में भारत की सामरिक ढाल बनेंगे।

आईएनए दिग्गज जयराज राजा ने पीएम मोदी को बताया 'महान', कहा-आपने भारत को नई ऊंचाई पर पहुँचाया

माले **(एजेंसी)**। इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) के दिग्गज जयराज राजा राव ने सोमवार को कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को याद किया और उन्हें 'महान' बताते हुए उनकी प्रशंसा की। जयराज राजा राव ने बातचीत में कहा कि मोदी ने भारत की छवि को कई क्षेत्रों में ऊँचा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दो-दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान रविवार को आईएनए के दिग्गजों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस सेना के ऐतिहासिक महत्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय डायस्पोरा के बीच इसके स्थायी प्रभाव को रेखांकित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आईएनए के दिग्गज जयराज राजा राव से भी मुलाकात की और इसे 'गहन रूप से प्रेरणादायक' बताया। आईएनए का ऐतिहासिक महत्व आज के मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा से जुड़ा है, क्योंकि यह सेना मुख्यतः इसी क्षेत्र में संगठित और विकसित हुई थी। इसके भीतर रानी झाँसी रेजिमेंट, एक महिला इकाई, विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिसमें कई भारतीय महिलाएँ शामिल थीं जिन्होंने कभी भारत नहीं देखा था, लेकिन भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखा।

जयराज राजा राव ने आईएएनएस को बताया कि वे भावुक स्वभाव के हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्हें भारत के एक महान प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने मोदी को एक 'ऊर्जावान और परवाह करने वाली' शख्सियत बताया और कहा कि उन्होंने भारत के गांवों में शौचालय, जल व्यवस्था और उनकी रखरखाव जैसी कई सामाजिक योजनाओं पर काम किया है। साथ ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तारीफ भी की। राव ने यह भी कहा कि मोदी ने सभी समुदायों मुस्लिम, हिंदू, ईसाई को बराबरी का दर्जा दिया और पाकिस्तान की उकसावे वाली हरकतों के खिलाफ भी मजबूत रुख अपनाया। उन्होंने अमेरिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका 'उकसावे वाला, साम्राज्यवादी और अत्यधिक दबंग' है, और भारत ने उसकी नीतियों से दूरी बनाए रखकर संतुलन बनाए रखा है।

जयराज राजा राव ने कहा कि उनके लिए यह मुलाकात भावनात्मक रूप से बहुत भारी थी क्योंकि प्रधानमंत्री ने 'एक साधारण व्यक्ति' से मिलने के लिए समय निकाला। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात का साझा विषय नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। राव ने कहा कि नेताजी ने उन्हें तब गले से लगाया था जब वे मात्र 12-13 वर्ष के थे, और प्रधानमंत्री भी नेताजी के प्रति बहुत आदर रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे 'मलेशियाई भारतीय' नहीं बल्कि 'भारतीय-मलेशियाई' हैं, और वे भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक देश में कई जातीय भारतीयों को एक साथ बनाए रखा यह एक शानदार उपलब्धि है।

यूरोप तक फैला एपस्टीन फाइलों का जहर फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने अहम पद से दिया इस्तीफा, बेटी भी जांच के घेरे में

पेरिस **(एजेंसी)**। एपस्टीन फाइलों का जहर अब यूरोप की राजनीति में भी फैलने लगा है। फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री और देश की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले जैक लैंग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों में उनका नाम 600 से अधिक बार सामने आया है। मामला सिर्फ नैतिकता का नहीं, बल्कि गंभीर टैक्स फ्रॉड और ऑफशोर मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक जांच तक पहुंच चुका है।यह खुलासा हाल ही में सार्वजनिक किए गए एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों के जरिए हुआ है। जैक लैंग ने पेरिस स्थित अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 86 वर्षीय जैक लैंग ने 7 फरवरी 2026 को अपना इस्तीफा सौंपा था। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 'इस्तीफे की पेशकश' बताया गया, जिसे 8 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

यह विवाद तब गहराया जब अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 जनवरी 2026 को जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक

कीं। इन दस्तावेज़ों की समीक्षा रॉयटर्स ने की, जिसमें सामने आया कि जैक लैंग का नाम लगभग 670 बार दर्ज है। एपी समाचार और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। इतनी बार नाम सामने आना अपने आप में असाधारण माना जा रहा है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए यह भी बताया कि अब नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी गई है।यह मामला अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधिकारिक पुष्टि के साथ राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। एपस्टीन फाइलों में जैक लैंग और उनकी बेटी दोनों के नाम उन संदिग्ध ऑफशोर लेन-देन में सामने आए हैं, जिनका संबंध सीधे जेफ्री एपस्टीन से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद फ्रांसीसी जांच एजेंसियों ने जैक लैंग और उनकी बेटी के खिलाफ 'एग्रेवेटेड टैक्स फ्रॉड लॉन्ड्रिंग' यानी गंभीर कर-चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के अनुसार, मामला केवल नैतिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि एपस्टीन से जुड़े ऑफशोर नेटवर्क का इस्तेमाल कर अवैध धन को छिपाया गया और टैक्स से बचने की कोशिश की गई।

फिलीस्तीनियों पर गिरी गाज, इजराइल ने वेस्ट बैंक को लेकर उठाया बड़ा कदम अब्बास ने फैसले को बताया 'खतरनाक'

तेल अबीब **(एजेंसी)**। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए एक नया निर्णय लिया है। इस फैसले का लक्ष्य वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की स्थिति को और मजबूत करना और फिलीस्तीनी प्राधिकरण की पहले से सीमित शक्तियों को और कमजोर करना बताया जा रहा है।दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के कार्यालय ने बयान जारी किया कि इस निर्णय से यहूदी बस्तियों के लिए फिलीस्तीनियों को जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम फलस्तीनी राष्ट्र के विचार को खत्म करना जारी रखेंगे।' निगरानी समूह 'पीस नाउ' के शोधकर्ता योनातन मिज़राची ने बताया कि इस फैसले को लागू करने के लिए वेस्ट बैंक के लिए इजराइल के शीर्ष कमांडर की मंजूरी की जरूरत होगी।

बांग्लादेश में भूकंप के झटकों से कांपी धरती ढाका दुनिया के 20 सबसे जोखिम वाले शहरों में शामिल

ढाका **(एजेंसी)**। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 3.3 रही और यह 45 किलोमीटर की गहराई पर आया। एनसीएस ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि यह भूकंप 9 फरवरी 2026 को सुबह

04:50 आईएसटी पर दर्ज किया गया। एनसीएस ने भूकंप का स्थान 25.08ष्टएन अक्षांश और 92.03ष्टई देशांतर पर बताया। इससे पहले 1 फरवरी को भी बांग्लादेश में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया था।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में बड़े भूकंप आने का जोखिम बहुत अधिक है, क्योंकि यह तीन सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट फॉल्ट्स के संगम पर स्थित है। दिसंबर 2025 में ढाका में 4.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद विशेषज्ञों ने कहा था कि तैयारी, जन जागरूकता और आधुनिक तकनीक से ही हानि को कम किया जा सकता है।बांग्लादेश भारतीय, यूरेशियन और बर्मा प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 6 सेंटीमीटर उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ती है, जबकि यूरेशियन प्लेट लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उत्तर की ओर बढ़ती है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)